रांची, बुधवार
25.02.2026
वर्ष : 11, अंक : 86 पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रुपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरें हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

वित्त मंत्री ने सदन में 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट किया पेश

महिलाओं और बच्चों के लिए 44 हजार करोड़

अबुआ दिशोम बजट 2026

झारखंड सरकार ने बजट सत्र के पांचवें दिन मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक लाख 58 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। बजट में कृषि गतिविधियों में लगी महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई। बजट 2026 में महिलाओं और बच्चों के लिए 44 हजार करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।

बाल बजट के लिए 10793 करोड़

इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 10 हजार 7 सौ 93 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 10.7 प्रतिशत है।

महिलाओं के लिए 34 हजार करोड़

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेन्डर बजट भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेन्डर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34 हजार 2 सौ 11 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है।

महिला खुशहाली योजना की शुरूआत

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग गरीब, किसान, आदिवासी और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि अबुआ दिशोम बजट झारखंडवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और गरीबों के आंसू पोंछेगा। महिला किसानों के लिए महिला

खुशहाली योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए सरकार 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वीबी-जी राम जी के कारण 5,640 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

वित्त मंत्री ने कहा कि दावा किया कि राज्य को केंद्रीय करों में 5,000 करोड़ रुपये का हिस्सा नहीं मिला और अनुदान सहायता के रूप में 11,000 करोड़ रुपये भी नहीं मिले। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी धीरे-धीरे घट रही है। वीबी-जी राम जी (अधिनियम) के कारण राज्य को 5,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कोयला आपूर्ति के बदले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

झारखंड
बजट 2026-झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रमुख आंकड़े साझा करते हुए दावा किया कि झारखंड लगातार संतुलित विकास और बेहतर वित्तीय अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

ग्लास ब्रिज और रोप वे का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पर्यटन के क्षेत्र में रांची जिलान्तर्गत दशम और जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज और रोप वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हुण्डरू जलप्रपात रोप वे का विकास कार्य कराया जाएगा। रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ-साथ पतरातु में स्काइवॉक एवं पतरातु जलाशय में सोलर बोट तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट का अधिष्ठापन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टॉवर का निर्माण एवं मैगनोलिया प्वाइंट में स्काइवॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिलान्तर्गत पुनासी डैम का पर्यटकीय विकास, पलामू जिलान्तर्गत मलय डैम का पर्यटकीय विकास, चतरा जिलान्तर्गत कोलेश्वरी पहाड़ में रोप वे का विकास एवं खूँटी जिलान्तर्गत पेरवाघाघ जलप्रपात तथा पांडु-पुडिंग पिकनिक स्थल के ईको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जाएगा।

चतरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना

झारखण्ड के सभी 17 राजकीय पोलिटेकनिक और 06 नवनिर्मित पोलिटेकनिक को आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर जेएचआईटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। झारखण्ड राज्य के चतरा जिला मुख्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का सकल बजट अनुमान है जो गत वर्ष से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 20 हजार 851 करोड़ 90 लाख पये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 9.2 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय अन्तर्गत गत वर्ष के बजट पर 8. 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 37 हजार 708 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रस्ताव है।

निवेश से 45 हजार को मिलेगा रोजगार

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच के माध्यम से झारखण्ड ने 01 लाख 24 हजार 230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए जिनसे इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में लगभग 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 हजार करोड़ का निवेश लाया जाएगा जिससे राज्य के लगभग 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।

महिला किसानों को मिलेगी मदद

वित्त मंत्री ने कहा कि महिला किसान खुशहाली योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीक की मदद दी जाएगी और ऑफलाईन एवं ऑनलाईन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 25 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है। गन्ना. जूट एवं अन्य नकदी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। इसके लिए पुरानी योजना को 'नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना' पुनर्नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 19 करोड़ 88 लाख रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक लैम्प्स-पैक्स में कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

अगले वित्त वर्ष में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इसके अलावा यहां देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर और रजरप्पा मंदिर जैसे धार्मिक स्थल के साथ-साथ नेतरहाट जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी हैं।

कैंसर रोग की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम

कैंसर रोग की रोकथाम के लिए झारखण्ड के सभी पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीईटी और सीटी स्कैन मशीन का अधिष्ठापन किया जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में ही ब्रेस्ट कैंसर रोग की पहचान कर लिए जाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 24 जिला सदर अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैथलैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से लोगों में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध करायी जाएगी।

नई सड़क परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़

वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 1644 कि0मी0 पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए पथों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 122 अदद् पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुलों के निर्माण कार्य हेतु 730 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने लिया व्यवस्था का जायजा

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 26 फरवरी को प्रस्तावित जमशेदपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय ने मंगलवार को संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट और निर्धारित रूट का व्यापक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
प्रशासनिक टीम ने कदमा स्थित श्री जगन्नाथ स्प्रीच्यूअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर और मनीपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थल की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की सघनता, मंच और अतिथि दीर्घा की तैयारी, आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग स्थल, मीडिया कवरेज के लिए निर्धारित स्थान, पेयजल और विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, अग्निशमन संसाधन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की विस्तार से जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी तैयारियां राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप समय पर पूरी की जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
इसके बाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से राष्ट्रपति के आगमन की संभावना है। वहां सुरक्षा घेरा, आगवानी स्थल, वीआईपी लाउंज और अन्य जरूरी प्रबंधों का निरीक्षण किया गया। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थलों तक निर्धारित रूट लाइन का भी बारीकी से अवलोकन किया गया। इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्ग, बैरिकेडिंग, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की योजना की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति का दौरा जिले के लिए गौरव का विषय है और इसे पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुबह 6 से रात 11 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक

जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था लागू की है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान कार, बस, ऑटो और भारी वाहनों सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति दो अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे दोपहर में सबसे पहले कदमा क्षेत्र जाएंगी, जहां निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम बारीडीह स्थित मणिपाल अस्पताल में प्रस्तावित है। दोनों स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और संबंधित मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति के दौरे को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यह आदेश उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया है।

अबुआ दिशोम बजट से विकास की रफ्तार होगी तेज

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला कल्याण को मिलेगा बल : संजीव

ग्रामीण विकास मद में वृद्धि यह दर्शाती है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों का विकास सरकार के मुख्य एजेंडों में है

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर : पोटका विधायक संजीव सरदार ने झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट शिबू सोरेन के सपने का झारखंड बनने की तरफ एक कदम है. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में विकासशील बजट दे कर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट कर दी हैं। विधायक ने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण विकास मद में वृद्धि यह दशार्ती है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार गांव, गरीब, पिछड़ा वर्ग, किसान, और आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के हित में है और विकास की इस मजबूत पहल से विपक्ष की निराधार आलोचना स्वतः शांत हो जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर : कीताडीह स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव, सुरक्षा प्रबंध, सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी मानक प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, उन्होंने कहा कि वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता व असावधानी नहीं बरती जाये, सीसीटीवी कैमरों की लगातार कार्यशीलता, रिकॉर्डिंग का समयबद्ध बैकअप संधारण तथा उसकी नियमित जांच अनिवार्य है।वेयर हाउस में दैनिक निरीक्षण रजिस्टर एवं लॉग बुक संधारण की प्रक्रिया पारदर्शी और अद्यतन रूप में हो। किसी भी परिस्थिति में अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की नियमित ऑडिट, रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समयबद्ध समीक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध रोधी संगठन की बैठक संपन्न

जमशेदपुर(बिभा) : अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध रोधी संगठन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 8 मार्च 2026 को महिला दिवस को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में संगठन के सदस्यों ने महिला अधिकारों और उनके उत्थान के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सिंह ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों को उजागर कर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके विकास में योगदान देना है।बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार रखे, और आगामी महिला दिवस के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई। इस बैठक में मुख्य रूप से गीता सिंह, फातिमा शाहीन, बी लक्ष्मी, रवि राज, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता उपस्थित थे।

कुएं में डूबने से वृद्ध महिला की मौत

रनिया(बिभा) । रनिया थाना क्षेत्र के अम्मा पकना गाँव निवासी बसंती देवी नाम की 62 वर्षीय वृद्ध महिला की मंगलवार को कुएँ में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घर के पास सब्जी की बारी के समीप बने कुएँ में बसंती देवी किसी काम से गई थी। इसी दौरान , अचानक पैर फिसलने से कुएँ में गिर गईं और डूब गईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों व ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें कुएँ से बाहर तो निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिसकी जानकारी परिवार जनों द्वारा रनिया पुलिस को दी गयी। वहीं सूचना मिलने पर, पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और जानकारी प्राप्त करते हुए यूडी केस दर्ज किया। साथ ही, मृत्यु समीक्षा पत्र भरकर मंगलवार को शव का अंत्यपरीक्षण कराया और परिजनों को सौंप दिया ।

झारखण्ड के अबुआ बजट पर खूँटी में लोगों की रही खट्टी मीठी प्रतिक्रिया

खूँटी (बिभा)। झारखंड सरकार के द्वारा मंगलवार को 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को 1लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। जिसपर जहाँ झामुमो और कांग्रेस के लोग इस बजट से खुश हैं तो वहीं भाजपा एवं अन्य लोग इस बजट को मीठा लोलीपॉप करार दे रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष आनन्द कुमार ने कहा कि ये बजट के बारे कुछ कहना ही बेकार है। पहले भी ये सरकार बजट लायी थी उसका तो हिसाब उनके ही पास नहीं है ?। अभी तक पिछले बजट को पूरा नहीं करके सरकार केवल हवाबाजी किया। मैया योजना का पैसा सभी लोगों को अभी तक नहीं दिया। और आशान्वित लोग कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। वहीं ठीकेदारों को अबतक बकाया पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इस बजट के बारे क्या कहें। जब पिछले वर्ष का बजट केवल बजट बनकर रह गया। वैसा ही यह बजट लोगों को लॉलीपोप दिखाने का मामला है। जिसे जनता जान गयी है। वहीं , इस बजट को झामुमो छात्र मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजु महतो ने इस आम बजट को संतुलित , विकासोन्मुखी, जनकल्याणकारी बजट बताया है।

महर्षि मेंही आश्रम मलियादा मुरहू पहुँचे ऋषिकेश आश्रम के स्वामी गंगाधर जी महाराज

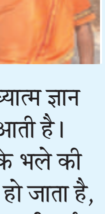

खूँटी (बिभा)। महर्षि मेंही आश्रम मलियादा मुरहू में मंगलवार को ऋषिकेश आश्रम के स्वामी गंगाधर जी महाराज का आगमन हुआ। जिनका भक्तिभाव के साथ उनका स्वागत किया गया। मौके पर, स्वामी जी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि देश और दुनिया में लोग निजस्वार्थ के लिए मानवीय मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज समाज में अध्यात्म ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अध्यात्म से ही सुख-समृद्धि आती है। जीवन में अच्छे विचारों का उदय होता है, और हम सबके भले की सोचते हैं। अच्छा कर्म करते हैं। आपसी भेदभाव समाप्त हो जाता है, भाईचारा कायम होता है। खासकर उच्च पदस्थ वर्ग, सत्ताधारी वर्ग और समाज सुधारकों को भेदभाव रहित सबके हित का काम करना चाहिए। मौके पर डॉ डीएन तिवारी, मोचीराय मुंडा, दिगंबर दास, रामहरि साव, ध्रुवेन्द्र भास्कर आदि उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के नेतृत्व में मतपेटिकाओं को वज्रगृह में रखा गया सुरक्षित

बिभा संवाददाता

खूँटी । नगर पंचायत क्षेत्र में सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त आर० रॉनिटा के नेतृत्व सारे मतपेटियों को बज्रगृह में सुरक्षित रख दिया गया है। जिसके दरवाजे को सील कर दिया गया है। जिसकी सुरक्षा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट रखें गये हैं। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।
ये बक्से उन उत्साहित युवा, महिला, वृद्ध एवं दिव्यांग सहित सभी वर्गों के मतदाताओं ने विकासित खूँटी निर्माण की दिशा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जो कि , प्राप्त जानकारी के अनुसार, खूँटी नगर पंचायत क्षेत्र में कुल मतदान प्रतिशत 64.78% रहा। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कदमा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति भवन में बनाएँ गये बज्रगृह में राज्य निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका के अनुरूप मतपेटिकाओं की रिसीविंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी मतदान कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतपेटिकाएँ ससमय जमा कराई गई। प्राप्त मतपेटिकाओं को सुरक्षित रूप से वज्रगृह में रखा गया। उक्त प्रकिया के दौरान उप विकास आयुक्त, सामान्य प्रेक्षक समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही उक्त वरीय पदाधिकारियों एवं अभियर्थियों तथा पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मतपेटिका को वज्रगृह में रखकर ताले को सील करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

कांकी गांव की 19 वर्षीय लड़की का फंदे से लटकता शव बरामद

खूँटी । प्रखंड क्षेत्र के कांकी गांव में मंगलवार की सुबह एक युवती की गाँव के ही पास के एक करंज पेड़ पर फंदे से लटकते हुए शव बरामद किया गया । युवती की पहचान सनिका मुण्डा की 19 वर्षीय बेटी कुवांरी कन्हाई के रुप में की गयी। जो अपने ओढ़ने से फंदा बनाकर झूल रही थी। शव देखते ही , ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। जिसे देख ग्रामीण और परिवार काफी दुखित हो गये। फिर , इस घटना के बारे खूंटी पुलिस को फोन पर जानकारी दी गई। जिसकी खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी लिया । तदोपरांत यूडी केस दर्ज करते हुए मृत्यु समीक्षा पत्र भरकर शव को अंत्यपरिक्षण कराने भेज दिया। जिसका अंत्यपरीक्षण कराया और परिजनों को सौंप दिया। साथ ही, पुलिस मामले का अनुसंधान में जूट गया है और पता लगाने के लिए लग गया है कि आखिर उसकी मृत्यु का कारण क्या था।

अम्मा पकना में घर के पास से टेम्पु की चोरी

बिभा संवाददाता

खूँटी । जिले के रनिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अम्मा पकाना मरचा सहित कई गाँवों में चोरी की घटना को चोर अंजाम देते रहे हैं । कहीं वाहन की चोरी तो कहीं घर व दुकान का ताला तोड़ना तो कहीं मवेशी चोरी आदि की घटनाओं से ग्रामीण परेशान और चिंतित रह रहे हैं।
इसी क्रम में मंगलवार की तड़के सुबह 03-04 बजे के बीच अम्मा पकना गाँव में जितेंद्र साहू सोमवार की शाम टेम्पु को घर के बाहर खड़ा किया था। वहीं मंगलवार की सुबह पाँच बजे के करीब उठकर बाहर निकला तो देखा कि उसका टेम्पु नजर नहीं आया। तभी उसके होश उड़ गए और चिंतित हो गया। जिसे अज्ञात चोरों ने चोरी कर उड़ा ले गये। जितेंद्र के अनुसार, मामला 4 बजे तड़के सुबह की हो सकती है। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह 5 बजे जब वह घर से बाहर निकला तो घर के बाहर ऑटो खड़ा नहीं मिला। इसके बाद उसने अपने स्तर से ऑटो की खोजबीन आसपास के क्षेत्र में किया परंतु कुछ पता नहीं चल पाया। टेम्पु चोरी होने से जितेंद्र के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसे चलाकर ही वह परिवार का भरण पोषण जितेंद्र करता था। जितेंद्र ने बताया कि सोमवार को दिनभर ऑटो चलाने के बाद रात को सात बजे के आसपास अपने घर के नजदीक ऑटो को खड़ा किया था। चोरी हुए ऑटो के संबंध में रनिया थाना ऑटो के मालिक जितेंद्र साहू ने लिखित आवेदन देकर ऑटो की खोजबीन में मदद पहुँचाने का गुहार लगाया है।

बागुनहातु में तीन दिवसीय बाल मेला में सैकड़ों बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, प्रतियोगिताओं और स्वास्थ्य शिविर का भी हुआ आयोजन

बिभा संवाददाता

जमशेदपुरः बागुनहातु स्थित दुर्गा पूजा मैदान में प्रसादचतुर्भुज फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बाल मेला हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। स्वर्गीय चतुर्भुज प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में चंद्रगुप्त सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर बाल मेला का विधिवत शुभारंभ किया और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दूसरे दिन आयोजित मैराथन एवं योग कार्यक्रम के दौरान सरयू राय, विधायक, जमशेदपुर पश्चिमी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित की और बैलून उड़ाकर मैराथन की शुरूआत कराई। इस अवसर पर टाटा फाउंडेशन से आदर्श गुप्ता ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन अत्यंत सराहनीय हैं और भविष्य में भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
तीनों दिनों में ड्रॉइंग, रंगोली, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, समूह नृत्य, बूगी-वूगी और मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास, ऊर्जा और उत्साह के साथ मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया।विजेता प्रतिभागियों को आनंद बिहारी दुबे जी द्वारा ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के सक्रिय सदस्यों और आयोजन समिति के सहयोगियों को भी सम्मान प्रदान किया गया।निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर बना आकर्षण का केंद्र बाल मेला के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र, दंत, शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई। तीन दिनों तक चले इस आयोजन ने न केवल बच्चों को आनंद और आत्मविश्वास दिया।

पीठासीन पदाधिकारी की डायरी एवं दस्तावेजों की संवीक्षा को लेकर हुई अभ्यर्थियों संग बैठक

बिभा संवाददाता

खूँटी । नगर पंचायत क्षेत्र में 23 फरवरी 2026 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न होने के पश्चात मंगलवार को पीठासीन पदाधिकारी की डायरी एवं अन्य निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रेक्षक रश्मि लकड़ा की उपस्थिति रही। साथ ही सभी निवार्ची पदाधिकारी, सहायक निवार्ची पदाधिकारी, एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं।
बैठक के दौरान 23 फरवरी को संपन्न हुए मतदान के कुल प्रतिशत की जानकारी साझा की गई। इसके अतिरिक्त वार्डवार हुए मतदान प्रतिशत की भी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों को दी गई।
बैठक में आगामी 27 फरवरी को होने वाली मतगणना की तिथि एवं समय के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मतगणना हेतु काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया, आवश्यक प्रपत्र, पहचान पत्र एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के बारे में भी अवगत कराया गया। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारियाँ साझा की गईं तथा किसी भी शंका के समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

27 फरवरी को होने वाले मतगणना को लेकर मतगणना कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

खूँटी । जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त आर० रॉनिटा के निर्देशानुसार नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 अंतर्गत मतगणना कार्य की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, खूँटी में मतगणना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। विदित हो कि 23 फरवरी को खूँटी नगर पंचायत क्षेत्र में हुए मतदान के पश्चात 27 फरवरी को कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में मतगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसी क्रम में प्रतिनियुक्त सभी मतगणना कर्मियों, यथा मतगणना सुपरवाइजर एवं मतगणना असिस्टेंट के लिए विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित कर मास्टर ट्रेनर द्वारा चरणबद्ध एवं गहन जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान मतपत्रों की गणना की विधि, टेबल प्रबंधन, अभ्यर्थियों/एजेंटों की उपस्थिति में पारदर्शिता बनाए रखने, मतगणना प्रपत्रों का सही संधारण, राउंडवार परिणाम संकलन, तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन संबंधी बिंदुओं पर विशेष रूप से विस्तार से समझाया गया।

जमशेदपुर ब्लड बैंक की टीम के साथ यूनियन की बैठक आयोजित

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर : आगामी 3 मार्च को होने वाले महा रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के सभी पदाधिकारी , तमाम ब्लड कोऑर्डिनेटर, जमशेदपुर ब्लड बैंक की टीम , आरके सिंह फैंस क्लब के सदस्य आदि मौजूद थे। बैठक में ब्लड बैंक के टीम का नेतृत्व संजय चौधरी कर रहे थे। उन्होंने रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विंदुओं, तैयारियों तथा अधिकाधिक संख्या में रक्तदान कराने आदि को लेकर सुझाव दिया।
बाद में बारी - बारी से तमाम लोगों ने अपने - अपने विचार व्यक्त किये। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि ब्लड बैंक की टीम शिविर में लगातार 16 घंटे से भी अधिक समय तक सेवा देती है यह पहल काबिले तारीफ है। उन्होंने टीम की सराहना करते हुए आयोजन में पहले से बेहतर सुविधा का भरोसा दिलाया। आगे उन्होंने कहा कि इस बार रक्तदाताओं का उत्साह देखते हुए तीन हजार यूनिट से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। जिसे सबों के सहयोग से हासिल करना है। उधर संजय चौधरी ने कहा कि यूनियन द्वारा आयोजित रक्तदान के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक की पूरी टीम यूनियन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस आयोजन को हर हाल में सफल बनाएंगे।

रांची, बुधवार
25.02.2026
वर्ष : 11, अंक : 86 पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरें हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस : राधाकृष्ण

बिभा संवाददाता

रांची। वित्त मंत्री राधा कष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।

वित्त मंत्री ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में विभिन्न विभागों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान करते हुए सरकार ने विकास की गति तेज करने और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ, हेमंत सरकार की ओर से अपने बूते राज्य के आंतरिक संसाधनों को सशक्त कर झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया गया है। इसी के तहत इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में बजट में लगभग 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावनाएं हैं। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 5,000 से 6,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा, जिससे लगभग 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावनाएं है।

इसी तरह आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में रेशम क्षेत्र में 1,800 मीट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बजट में कुटीर उद्योग के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने के प्रावधानों को शामिल है। प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए रांची स्थित श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में 155 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की बातें बजट में कही गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन निर्माण विभाग के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए कुल 2 लाख 11 हजार 10 आवासीय इकाइयां स्वीकृत किए गए है। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास योजना के तहत 36 हजार 202 तथा भागीदारी आधारित किफायती आवास योजना के तहत 36 हजार 740 निमार्णाधीन आवास पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत आदित्यपुर, सिमडेगा, हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजनाओं तथा चास सेप्टेज प्रबंधन योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए है। नौ निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को स्वीकृति तथा छह लिगेसी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य बजट में शामिल किया गया है। वहीं 14 जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए तीन हजार 919 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।

अन्य विभागों के लिए बजट प्रावधान के तहत पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-शासन के लिए 328 करोड़ 99 लाख रुपये, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये, योजना एवं विकास विभाग के लिए 539 करोड़ 94 लाख रुपये, वन विभाग के लिए एक हजार 544 करोड़ 75 लाख रुपये, पथ निर्माण विभाग के लिए छह हजार 601 करोड़ 28 लाख रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5 हजार 81 करोड़ 74 लाख रुपये, नागर विमानन के लिए 138 करोड़ 63 लाख रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 11 हजार 197 करोड़ 89 लाख रुपये राशि शामिल किए गए है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा और कल्याण विभाग के तहत साइकिल वितरण योजना के तहत 136 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1,216 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए तीन हजार 568 करोड़ 19 लाख रुपये निर्धारित है। जबकि प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16 हजार 251 करोड़ 43 लाख रुपये, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 564 करोड़ 45 लाख रुपये, सात जिलों में 12 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करने की बातें शामिल है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में रिम्स में एमबीबीएस सीटों को दोगुना करने का लक्ष्य, अगले वर्ष रिम्स सहित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 220 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी करने, आगामी चार वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,030 से दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना शत-प्रतिशत राज्य योजना से संचालित किए जाने, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सात हजार 990 करोड़ 30 लाख रुपये, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए पांच हजार 194 करोड़ 53 लाख रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 62 लाख 55 हजार ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य करने, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए दो हजार 887 करोड़ 27 लाख रुपये किए जाने की बातें शामिल है। ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा मामलों के विभागीय बजट में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए एक हजार 168 करोड़ 73 लाख रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 12 हजार 346 करोड़ 90 लाख रुपये, पंचायत ज्ञान केंद्रों के लिए 209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। 15वें वित्त आयोग से एक हजार 340 करोड़ रुपये अनुदान मिलने के प्रावधान है। महिलाओं, बच्चों एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 22 हजार 995 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किए गए है। मंत्री ने कहा कि इसी तरह बजटीय प्रावधान में गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों के लिए कई अन्य बेहतर प्रावधान किए गए है ताकि राज्य का सर्वांगिण विकास हो सके।

बजट में हर वर्गों का रखा गया है ख्याल, जमीन पर दिखेगा परिणाम : हेमंत सोरेन

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वित्त मंत्री ने राज्य के बेहतर विकास को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ बजटीय प्रावधानों को सदन पटल पर लाया है। इस बजट में राज्य सरकार ने हर वर्ग के लोगों के साथ-साथ हर किसी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बजट पास किया है। जमीनी स्तर पर इसका जल्द परिणाम दिखने को मिलेगा, ताकि राज्य का सर्वांगिण विकास हो सके।

सोरेन मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जिस बजट की कॉपी को रखी गई। मीडिया के माध्यम से उसे सार्वजनिक किया गया है। बजट में लाई गई हर चीजों को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी को नजर अंदाज नहीं किया है। उन्होंने एयर एंबुलेंस के जरिए इलाज कराने के दौरान विमान हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि बेहतर इलाज करवाने के लिए सवार लोगों ने एयर एंबुलेंस किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जानें चली गई। लेकिन सारी चीजों की सूचना जबसे मिली है प्रशासन हरकत में है। सकारात्मक कदम उठाई जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

अश्लील कंटेंट पर सरकार सख्त, पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई। बंद किए गए प्लेटफॉर्म्स में मूड एक्स वी आई पी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और बिना उचित कंटेंट मॉडरेशन के अश्लील सामग्री उपलब्ध करा रहे थे। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। मंत्रालय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगी।

केंद्र ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नए सेवा तीर्थ में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल जून में राज्य सरकार ने राज्य का नाम केरलम किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था।

झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर हुआ एमओयू

व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण विकास सहित हरेक क्षेत्र में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर मंगलवार को एमओयू हुआ। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक एवं राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक आज राज्य सरकार के साथ एक नए अध्याय के रूप में जुड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के साथ-साथ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक लेन-देन की कड़ी में बैंक की अहम भूमिका होती है। वर्तमान समय में व्यवसाय,कृषि,ग्रामीण विकास सहित हरेक क्षेत्र में बैंक की बड़ी भूमिका होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों के साथ-साथ कई संस्थानों की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसी क्रम में आज राज्य सरकार एवं पंजाब नैशनल बैंक के बीच एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। इससे पहले भी राज्य सरकार एवं अन्य बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं और उक्त एमओयू के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार के साथ जुड़ी है उस उद्देश्य और कर्तव्य को सफलता पूर्वक पूरा करेगी। राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के बेहतर समन्वय का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित आम जनमानस को भी मिलेगा।

यह बातें श्री सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित झारखंड सरकार एवं पंजाब नैशनल बैंक के मध्य राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में अपने संबोधन में कही।

मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से एमओयू हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों एवं कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की,मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक आशीष कुमार चतुर्वेदी,मंडल प्रमुख अवधेश झा,उप मंडल प्रमुख राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित राज्य सरकार के अन्य अधिकारी एवं पंजाब नेशनल बैंक के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट : नियम विरूद्ध निजी नर्सिंग कॉलेजों में नामांकित छात्रों को परीक्षा में बैठने की मिलेगी अनुमति

बिभा संवाददाता

रांची। राज्य के विभिन्न निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से पूर्व में नामांकित छात्रों को राज्य सरकार राहत देगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए तय नियमों को एक बार शिथिल करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से वैसे छात्र जो झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) की ओर से काउंसिलिंग के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से नामांकित कर लिए गए थे।

कैबिनेट के फैसले से ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सकेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से अपनी संस्था को तकनीकि मान्यता नहीं मिलने सहित अन्य अनियमितताओं के बावजूद नर्सिंग कोर्स में नामांकन ले लिया था। इस वजह से झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) की ओर से उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही थी। ऐसे नामांकित छात्रों की वर्षों से परीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब राज्य सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद ये सभी छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे और नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

इधर, निकाय चुनाव के कारण मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गये फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें से एक फैसले को स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट के फैसलों में लगभग 12 फैसले न्यायालय के आदेश से संबंधित थे।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की एयर एम्बुलेंस दुर्घटना की समीक्षा, कहा-होगी उच्च स्तरीय जांच

बिभा संवाददाता

चतरा/रांची। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एयर एंबुलेंस क्रैश में सात लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मंगलवार को चतरा सदर अस्पताल पहुंचे और स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।

स्वास्थ्य मंत्री ने जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर मामला विमानन सुरक्षा मानकों और उड़ान संचालन प्रक्रिया से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। विशेषज्ञ टीम को जांच के लिए बुलाया गया है।

मंत्री ने बताया कि ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) की गहन जांच की जाएगी। इसके साथ ही मौसम की स्थिति, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और पायलटों के अनुभव की भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि तकनीकी जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी, जो ब्लैक बॉक्स बरामद करने का प्रयास करेगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

दरअसल, रांची से दिल्ली जा रही रेडबर्ड एयरवेज प्रा. लि. की एयर एंबुलेंस सोमवार देर रात चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कसियातु जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने देर रात तक सभी शव बरामद कर लिए थे।

विमान ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ समय बाद कोलकाता एटीसी से संपर्क टूट गया, जिसके बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय किया गया। खोजबीन के दौरान विमान का मलबा कसियातु जंगल में मिला। विमान में दो पायलट कैप्टन विवेक और कैप्टन सबराजदीप के अलावा मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी, भगीना ध्रुव कुमार, डॉ. विकास कुमार गुप्ता तथा पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खराब मौसम को हादसे का संभावित कारण माना गया है। सोमवार देर शाम अचानक मौसम बिगड़ गया था। तेज हवा और झमाझम बारिश के बीच विमान अपने निर्धारित रूट से दाईं ओर डायवर्ट हो गया और संभवतः रास्ता भटक गया। ग्रामीणों ने जंगल से तेज धमाके की आवाज सुनने के बाद पुलिस-प्रशासन को सूचना दी।

बताया जा रहा है इस हादसे में मृतक संजय कुमार चंदवा के निवासी और व्यवसायी थे। पलामू स्थित उनके लाइन होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वे लगभग 65 प्रतिशत तक झुलस गए थे। उन्हें रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। उनके दो बेटे शुभम (17) और शिवम (13) हैं।

संजय के परिजनों के अनुसार, एयर एंबुलेंस सेवा के लिए कंपनी को पहले ही 8 लाख रुपये दिए जा चुके थे, जबकि 2.50 लाख रुपये शेष थे। आरोप है कि पूरी राशि नहीं मिलने पर कंपनी ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया था। बाद में परिजन चंदवा जाकर शेष राशि की व्यवस्था कर दोबारा रांची लौटे और भुगतान के बाद ही विमान ने उड़ान भरी।

बहरहाल, इस हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। राजनेताओं ने भी शोक-संवेदना वयक्त की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। झारखंड के पूर्व श्रम मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी घटना को दुखद बताते हुए सभी मृतकों के परिजनों को समान मुआवजा देने की मांग की है।

मृतकों में शामिल डॉ. विकास कुमार गुप्ता के पिता ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि रांची में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं, तो इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़ता।

पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा के भाई ने भावुक होकर कहा, ˛मेरा छोटा भाई मेरे लिए सब कुछ था। पिता के निधन के बाद वही मेरा एकमात्र सहारा था।˛ उन्होंने बताया कि सचिन कई वर्षों से नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में कार्यरत थे और पिछले दो-तीन वर्षों से एंबुलेंस सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बीच राज्य सरकार ने सरकार ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। हादसे की आधिकारिक जांच जारी है और पूरे राज्य में शोक का माहौल है।

सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड मीडिएटर बनाए गए डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉ. गंगवार

अब शांतिदूत बन सुलझाएंगे उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न कोर्ट के न्यायिक विवाद

बिभा संवाददाता

बोकारो : शिक्षा के क्षेत्र में विगत साढ़े तीन दशक से सेवारत दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बोकारो के प्राचार्य डॉ. अवनीन्द्र सिंह गंगवार की उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। डॉ. गंगवार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलहनामा परियोजना समिति (एमसीपीसी) की ओर से मध्यस्थता की अवधारणा एवं तकनीक पर आयोजित 40 घंटे के विशेष प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। 18 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक हाइब्रिड मोड में चले इस गहन सत्र के उपरांत मंगलवार को विद्यालय परिवार ने इसके लिए उन्हें बधाई दी और इसे संस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने इसे पूरे झारखंड के शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा गौरव बताया।

इस प्रशिक्षण के साथ ही अब डॉ. गंगवार शिक्षाविद के साथ-साथ एक शांतिदूत की भूमिका में न्यायिक विवादों को सुलझाने में भी अपनी महती भूमिका निभा सकेंगे। एक सर्टिफाइड मीडिएटर (प्रमाणित मध्यस्थ) के रूप में भी अब वे पहचाने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रमाणन के साथ ही वे विभिन्न न्यायालयों (जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या स्वयं सुप्रीम कोर्ट) के मध्यस्थता केंद्रों में पैनलबद्ध हो चुके हैं। यानी, कोर्ट खुद ऐसे मामलों को उनके पास भेज सकता है, जिन्हें आपसी बातचीत से सुलझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिष्ठित समिति (एमसीपीसी) के प्रशिक्षकों - इला रावत एवं राजीव ठकराल के मार्गदर्शन में प्राप्त यह दक्षता मात्र एक प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि शिक्षा और न्याय के समन्वय की नई दिशा है। आम भाषा में समझें तो मीडिएशन का मतलब है दो पक्षों के बीच के झगड़े या विवाद को बिना कोर्ट-कचहरी जाए, बातचीत और सही तकनीक से सुलझाना। सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन एंड कॉनसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी देशभर में ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार करती है, जो कानूनी दांव-पेंच के बजाय आपसी सहमति से समाधान निकाल सकें। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मानकों के अनुरूप यह ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है, ताकि विवादों को समय रहते मध्यस्थता व सुलहनामे से खत्म किया जा सके। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डॉ. गंगवार ने सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे केवल एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक गंभीर जवाबदेही बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित करना है, जिसे अब वे न्याय के इस मानवीय पहलू (मध्यस्थता) के जरिए और भी सशक्त बनाएंगे। उनका मानना है कि अधिकांश विवादों का स्थाई हल कानूनी फैसलों से कहीं अधिक आपसी संवाद में छिपा होता है। उन्होंने कहा कि अपनी इस नई भूमिका के जरिए वे कड़वाहट की जगह सहयोग और विवाद की जगह विश्वास का वातावरण बनाने के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित हो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

नशे में थार ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश, चार गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

बोकारो। गरगा पुल चेकपोस्ट पर पुलिस चेकिंग के दौरान नशे में धुत चालकों ने हंगामा मचाया। 'पापा' लिखी थार ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर दोनों वाहनों से चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे एयरपोर्ट की ओर से आ रही काली थार (जेएच09बीएन 4141) को रोकने का इशारा करने पर चालक ने रफ्तार बढ़ाई। नंबर प्लेट पर डिजाइन करके 'पापा' लिखा था। चालक ने बैरिकेडिंग को ठोक दिया और भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी कूदकर बाल-बाल बचे। पीछा कर वाहन रोका गया। जांच में चालक शराब के नशे में धुत मिला। थार सवार दोनों को गिरफ्तार किया गया। बीएस सिटी थाना में कांड संख्या 33/26 दर्ज, बीएनएस की धाराओं व एमवी एक्ट 185 के तहत केस। उसी चेकपोस्ट पर टाटा पंच (जे एच 09बी ए 5612) को रोका तो चालक व एक सवार नशे में उलझ पड़े। जब्ती प्रक्रिया पर बाधा डाली। दोनों गिरफ्तार, कांड संख्या 34/26 दर्ज।पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर थाने में खड़े किए। चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में। बोकारो पुलिस ने नशे में वाहन चलाने व सरकारी काम में बाधा पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।

बोकारो के प्रभात कॉलोनी में व्यवसाई सोनू मिश्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा

बिभा संवाददाता

बोकारो : बोकारो के प्रभात कॉलोनी में इनकम टैक्स विभाग की पटना इकाई ने व्यवसाई सोनू मिश्रा के आवास और प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। करीब 10 अधिकारियों की टीम चार इनोवा गाड़ियों से पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।सूत्रों के अनुसार, छापेमारी 'बाला पेंटिंग' से जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर की गई है। टीम दस्तावेजों, रजिस्टरों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।प्रभात कॉलोनी में पहुंचते ही टीम ने इलाके को घेर लिया। व्यवसाई सोनू मिश्रा से पूछताछ की जा रही है।

छापेमारी जारी है और आगे की कार्रवाई अपेक्षित है।बोकारो के प्रभात कॉलोनी में इनकम टैक्स विभाग की पटना इकाई ने व्यवसाई सोनू मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी चलाई।चार इनोवा गाड़ियों से पहुंची 10 अधिकारियों की टीम 'बाला पेंटिंग' से जुड़े आयकर के लेन-देन की जांच कर रही है। दस्तावेज जब्त कर पूछताछ जारी। स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया।

रेल गार्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

बोकारो(बिभा)। दुग्दा रेलवे कॉलोनी निवासी सह रेलवे गार्ड सिदिकी अंसारी उम्र लगभग 50 बर्षीय का सोमवार रात्रि को जारंगडीह रेलवे स्टेशन में ड्यूटी के दौरान रेलवे इंजन के चपेट में आने से मौत हो गयी। बताते चलें कि रेलवे गार्ड सिदिकी अंसारी जारंगडीह रेलवे स्टेशन में ड्यूटी कर चंद्रपुरा आने के क्रम में इंजन पर चढ़ने के क्रम में पैर फिसल जाने से पटरी पर इंजन के नीचे चला गया ।जिससे उनकी कमर कट गया।जहाँ उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मृत के शव को अंतपरीक्षण हेतु धनबाद भेजा। अंतपरीक्षण के बाद मृतक का शव उनके परिजनों को सौप दिया।मृतक सिदिकी अंसारी मूलरूप से झारखंड के जामताड़ा का निवासी बताया जाता हैं। मृतक रेलवे गार्ड सिदिकी अंसारी अपने पीछे पत्नी समेत दो पुत्री और एक पुत्र छोड़ गए।

बोकारो रेलवे स्टेशन पर गोली मार हत्या का खुलासा
मुख्य आरोपी बलराम उर्फ भोलू गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

बोकारो : बोकारो रेलवे स्टेशन के टेम्पो स्टैंड के पास 22 फरवरी 2026 की रात सात बजे के आसपास सचिन यादव नामक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मात्र एक दिन बाद मुख्य आरोपी बलराम कुमार उर्फ भोलू विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, मोबाइल फोन और जैकेट बरामद कर लिया।

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के छोटे भाई मिथलेश कुमार ने रेल थाना बोकारो में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कांड संख्या-05/26, 23 फरवरी 2026 को धारा 103(1)/3(5) इठर एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी बलराम ने पूछताछ में कबूल किया कि एक माह पूर्व मृतक सचिन और उसके साथियों ने उसके जीजा धनंजय कर्मकार के साथ मारपीट की थी, उसी पुरानी रंजिश के चलते विवाद बढ़ा।

उस रात आरोपी अपने जीजा के साथ स्टेशन पर पहुंचा, जहां सचिन से बहस हुई और गुस्से में उसने गोली मार दी। घायल सचिन को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, स्टेशन परिसर में उउळश फुटेज भी इस घटना को दर्ज कर चुकी है।

कांड की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेल जमशेदपुर ने पुलिस उपाधीक्षक रेल चक्रधरपुर मनीष कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की। टीम ने मनसा सिंह गेट के पास से 26 वर्षीय बलराम कुमार उर्फ भोलू विश्वकर्मा, पिता स्व. धनेश्वर विश्वकर्मा, निवासी रेलवे गोल मार्केट, थाना बालीडीह, बोकारो को दबोच लिया। उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल मैगजीन सहित - 1पहना हुआ उजला रंग का जैकेट - 1मोबाइल फोन - 1 आरपीएफ बोकारो और बालीडीह जिला बल के सहयोग से यह सफलता हासिल हुई।

गिरफ्तार बलराम का लंबा अपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें बालीडीह थाना और आरपीएफ पोस्ट बोकारो में कुल 15 मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, रंगदारी, अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस की छापेमारी दल में शंकर प्रसाद, पु.नि. सह थाना प्रभारी, रेल थाना बोकारो ,बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, पु.नि. सह , आरपीएफ पोस्ट कमांडेंट संतोष कुमार ,बोकारो पु.अ.नि. सह थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, रेल थाना मुरी दिलिप कुमार, पु.अ.नि. रेल थाना बोकारो अन्य सशस्त्र बल। पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया है

संक्षिप्त खबरें

संगीतज्ञ कृष्ण दुलारी पाठक की याद में सजी सुरों की महफिल

बोकारो(बिभा): बोकारो के जाने-माने संगीतज्ञ पं बच्चन जी महाराज के संयोजन में उनकी मां व भजन गायिका स्व. कृष्ण दुलारी पाठक की पुण्यतिथि पर आदर्श कोआपरेटिव कॉलोनी में संगीत संध्या आयोजित कर उन्हें स्वरमयी श्रद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम की शुरूआत स्व. कृष्ण दुलारी पाठक की तस्वीर पर पं बच्चन जी महाराज, उषा रानी पाठक व कलाकारों द्वारा माल्यार्पण व पुष्पार्चन से हुई। गायक व कवि ब्रह्मानंद गोस्वामी, अरुण पाठक, उमेश कुमार झा, दीप नारायण गोस्वामी, चंद्र कान्त शर्मा, कृष्णा तुलसी, आरोही मिश्रा, आद्विका मिश्रा, अर्कदेव आचार्य व अन्य कलाकारों ने शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भजन, होली आदि की सुमधुर प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरोही मिश्रा व आद्विका मिश्रा ने राग यमन में पिया की नगरिया..., कृष्णा तुलसी ने भजन, अरुण पाठक ने दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां..., मैथिली में होली गीत होली कनक भवन में खेलथि सिया रघुवीर.., मैथिली नचारी पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी.. की भावपूर्ण प्रस्तुति से सबकी वाहवाही ली। कार्यक्रम में तबले पर पं बच्चन जी महाराज, राजू गोस्वामी व अश्विनी कुमार, की बोर्ड पर सदय कुमार झा, हारमोनियम पर चंद्रकांत शर्मा, दीप गोस्वामी, बीएन गोस्वामी ने संगति की। इस अवसर पर आदर्श कोऑपरेटिव के निदेशक विनोद कुमार, गीता देवी, गायिका अंकिता पाठक, अनुपमा पाठक आदि उपस्थित थे।

रोटरी प्ले ग्रुप में धूमधाम से मनाया गया रोटरी इंटरनेशनल का 121वां स्थापना दिवस

बोकारो(बिभा) : रोटरी क्लब ऑफ बोकारो स्टील सिटी के रोटरी प्ले ग्रुप ने 23 फरवरी को रोटरी इंटरनेशनल के 121वें स्थापना दिवस को उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया।कार्यक्रम की शुरूआत सचिव रोटेरियन घनश्याम दास ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने बताया कि 1905 में पॉल हैरिस और उनके तीन साथियों द्वारा शुरू हुए इस छोटे समूह ने आज 'सेवा सर्वोपरि' के मंत्र के साथ विश्वभर में 14 लाख से अधिक सदस्यों वाला वैश्विक मानवीय संगठन बन लिया है।मुख्य अतिथि रोटेरियन डॉ. अनिल त्रेहान ने रोटरी की 121 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पर प्रकाश डालते हुए पोलियो उन्मूलन, शांति स्थापना, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रोटरी स्थानीय व वैश्विक स्तर पर समुदायों में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है।केक काटकर कार्यक्रम का समापन हुआ, उसके बाद सदस्यों ने 'हैप्पी 121वां बर्थडे' का सामूहिक उद्घोष कर सेवा के प्रति नया संकल्प लिया।उपस्थित सदस्यों में रोटेरियन डॉ. राजदीप, डॉ. अनिल त्रेहान, अशोक तनेजा, अशोक केडिया, देबाशीष साहाना, प्रदीप सिंह, संजय जैन, जतिन अग्रवाल, पूनम त्रेहान, संध्या राज, सुनीता जैन, नीलम दास और मानसी साहाना शामिल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉ. राजदीप का विशेष योगदान रहा।

लुगु बुरु पहाड़ पर हाथियों का झुंड, आसपास के 15 गांवों में हाई अलर्ट

बोकारो (बिभा): लुगु बुरु पहाड़ पर हाथियों की मौजूदगी के कारण आसपास के गांवों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग अधिकारी संदीप शिंदे ने चेतावनी दी है कि हाथी झुंड किसी भी समय पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। प्रभावित गांवों के निवासियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।लुगु बुरु और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हाथी झुंड की निगरानी वन विभाग की टीमें कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, हाथी रात के समय तेज गति से चलते हैं और भोजन की तलाश में घरों तक पहुंच सकते हैं। विभाग ने चोरगावा, मुरपा, खाखंडा, गंगपुर, बेलडीह, तुलबुल, पिंडरा, तुतिझरना, डकासाडम, सेहेदा, तिलैया, नारण, लवालांग, अंबाडीह और केरी गांवों के निवासियों को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है।सुरक्षा निर्देशों पर जोर वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:रात के समय घरों के अंदर रहें और बाहर न निकलें।हाथियों के नजदीक आने पर पक्के मकान या उसकी छत पर शरण लें, क्योंकि छत सबसे सुरक्षित विकल्प है।फसल या मकान को नुकसान होने पर विभाग त्वरित मुआवजा प्रदान करेगा।मुआवजे और सहायता के लिए संपर्क नंबरःलुगु बुरु एवं झुमरा क्षेत्रः अजीत मुर्मू (8797380577) महुआटांड़ एवं बरकी पुन्नू क्षेत्रः निताई चंद्र महतो (7070466084)पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए विभाग ने सतर्कता पर बल दिया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

दो दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ

बिभा संवाददाता

बोकारो । बोकारो के सेक्टर 12 क्लब मोड़ के निकट श्रीराम क्लब सेवा समिति द्वारा आज कलश यात्रा एवं श्री हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ दो दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीराम क्लब सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष रिंकू सिंह ने बताया कि श्री हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहां विशाल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया है।जहाँ विद्वान पंडितों ने बैदिक मन्त्रोंच्चारण के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी है।

श्री सिंह ने कहा कि ऐसे अध्यात्मिक आयोजन से शहरवासी एक जगह एकत्रित होकर भजन करो भोजन करो के आध्यात्मिक जुटान से पूरे क्षेत्र का वातावरण पूर्ण रूप से भक्तिमय हो गया है।जयघोष के साथ भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर दो दिवसीय संकीर्तन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि संकीर्तन एवं पूजा अर्चना राज्य और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु संगठित होने का सशक्त माध्यम है।संगीतमय संकीर्तन से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा।महायज्ञ को सफल बनाने में दिनेश पांडेय, चुमन कुमार, अमरनाथ पोद्दार,सोमेश पाण्डेय,भरत यादव, संतोष वरनवाल, संतोष कुमार,रंजय कुमार,शिव कुमार, गौरव कुमार,पिंटू (अयोध्या कुमार), श्री राम जी, शैलेश कुमार, पप्पू कुमार,गोलू कुमार, रंजय, गौतम,गौरव, शांतनु चौहान,राजु जी,रंजय जी,प्युष अनिल कुमार ,विशाल,अजय आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मतगणना केन्द्र में मोबाइल पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : उपायुक्त

बिभा संवाददाता

बोकारो। चास स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में बनाए गए मतगणना केंद्र का जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरविंदर सिंह, उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 अंतर्गत चास नगर निगम एवं फुसरो नगर परिषद की मतपेटियों की गणना हेतु चिन्हित मतगणना हॉल का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक मतपेटियों के सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। साथ ही, निवार्ची पदाधिकारी, अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत अभिकताओं के प्रवेश एवं निकासी मार्गों को अलग-अलग सुनिश्चित करने, अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित रखने तथा बैरिकेटिंग को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के क्रम में मीडिया कर्मियों के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर, चिकित्सीय सहायता हेतु मेडिकल टीम की तैनाती तथा हेल्प डेस्क की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया प्रतिनिधियों को सुगम सूचना उपलब्ध कराने, पेयजल, शौचालय एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस एवं प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल डीईओ सह डीसी द्वारा अनुमति प्राप्त पदाधिकारी/मतगणना कर्मी ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, प्राधिकृत मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त *किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी।

मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को समय से पूर्व उपस्थित होने, पहचान पत्र अनिवार्य रूप से धारण करने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मशीन शॉप की रोल ग्राइंडिंग मशीन का नवीनीकरण

बिभा संवसाददाता

बोकारो : बोकारो इस्पात संयंत्र के मशीन शॉप में स्थापित जर्मन निर्मित रोल ग्राइंडिंग मशीन का विद्युत एवं यांत्रिकी अनुरक्षण टीम द्वारा सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया गया. पिछले कुछ महीनों से यह मशीन परिचालन संबंधी गंभीर बाधाओं एवं जाम होने की समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके कारण इसका संचालन अत्यंत कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गया था. इन तकनीकी समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु संयंत्र की आंतरिक टीम ने इस मशीन के पूर्ण कायाकल्प की पहल की.

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अधिशासी निदेशक (संकार्य) श्री अनुप कुमार दत्त, मुख्य महाप्रबंधक (अनुरक्षण) श्री शरद गुप्ता तथा मशीन शॉप के विभागाध्यक्ष श्री पी. पी. सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्राप्त की गई.

इस चुनौतीपूर्ण कार्य को मशीन शॉप के वरीय प्रबंधक श्री शुभलेन्दु कुमार, श्री नितिन सक्सेना तथा सहायक प्रबंधक श्री मनोज कुमार द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. इस परियोजना में श्री हरिहर राउत, महाप्रबंधक (ईटीएल), श्री अनिंद्य पाल, सहायक महाप्रबंधक (ईआरएस) तथा श्री नवीन कुमार, वरीय प्रबंधक (ईआरएस) का तकनीकी सहयोग सराहनीय रहा. मशीन शॉप से इन कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक महाप्रबंधक श्री डी. के. मंडल द्वारा किया गया.

नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान यांत्रिकी टीम ने मशीन के समस्त हिस्सों को खोलकर उनकी गहन ओवरहॉलिंग की और जाम होने की समस्या को जड़ से समाप्त किया. इसके साथ ही मशीन के गियरबॉक्स का भी पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया. दूसरी ओर, विद्युत अनुरक्षण टीम ने ईटीएल एवं ईआरएस विभागों के सहयोग से मशीन के प्रमुख घटकों जैसे कंट्रोल केबल्स एवं रिले लॉजिक सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया.

मशीन शॉप की इस पहल से न केवल रोल ग्राइंडिंग मशीन की कार्यक्षमता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, बल्कि इससे मशीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई है. आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया गया यह नवीनीकरण कार्य संयंत्र की उत्पादकता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बीएसएल की आत्मनिर्भरता एवं तकनीकी उत्कृष्टता को प्रतिबिंबित करता है.

सेल कर्मचारी संघ ने सीटीसी मीटिंग में धांधली का लगाया आरोप, प्रबंधन से की पारदर्शिता की मांग

बिभा संवाददाता

बोकारो : बीएसएल अनाधिकारी कर्मचारी संघ ने सेल कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यकारी निदेशक राजीव पांडेय को कड़ा पत्र लिखकर सीटीसी (कंपैशनेट ट्रांसफर कमेटी) मीटिंग में हो रही धांधली रोकने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। संघ का आरोप है कि सेल प्रबंधन कंपनी की नीतियों की अनदेखी कर अधिकारियों की निजी इच्छा से फैसले ले रहा है, जिससे कर्मचारियों का विश्वास उठ रहा है। संघ अध्यक्ष हरिओम ने बताया कि अनुकंपा आधारित स्थानांतरण के लिए गठित सीटीसी कमेटी की बैठकें न तो तय समय पर होती हैं और न ही उनके परिणाम पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाते। एक ही प्रकृति के आवेदनों पर मनमाने फैसले लिए जाते हैं, बिना कोई आधार बताए। उदाहरण के तौर पर, 17 फरवरी 2026 को हुई मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 11 अप्रैल 2025 के बाद करीब 10 माह बाद आयोजित हुई, जबकि नियम के मुताबिक हर तीन माह में बैठक होनी चाहिए। हरिओम ने आगे कहा, अस्वीकृत आवेदनों का कारण, अस्वीकृति देने वाले यूनिट या अधिकारियों के नाम न सीटीसी पोर्टल, न केयर पोर्टल और न ही एचआरएमएस पोर्टल पर बताए जाते हैं। आवेदकों को व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं दी जाती। संघ ने मांग की है कि 17 फरवरी की मीटिंग के मिनट्स जारी किए जाएं, सभी आवेदकों को फैसले का आधार बताया जाए और भविष्य में हर तीन माह में सीटीसी मीटिंग सुनिश्चित हो। संघ का कहना है कि इस गुप्त और गलत प्रक्रिया से सेल प्रबंधन पर कर्मचारियों का भरोसा खत्म हो रहा है। प्रबंधन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 12,347 करोड़ रुपये का बजट : दीपिका पांडेय

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास कार्य एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026झ्र27 में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ाकर 12,347 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, आजीविका सृजन, आवास योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में सहायक होगा।
मंत्री मंगलवार को विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गांवों की तस्वीर बदलने और ग्रामीणों के जीवन में ठोस सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयासरत है, ताकि झारखंड देश के मानचित्र पर एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हो सके।
मंत्री ने बताया कि केवल ग्रामीण कार्य विभाग का बजट 4,576 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,081 करोड़ रुपये किया गया है। यह राशि ग्रामीण सड़कों, पुल-पुलियों और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने में खर्च की जाएगी। इससे दुर्गम गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग का बजट 2,144 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,283 करोड़ रुपये किया गया है। यह प्रावधान पंचायतों को सशक्त बनाने, पंचायत सचिवालयों को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए संचालित 250 योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने इस बार लगभग 34,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जेंडर बजटिंग को 35 प्रतिशत तक ले जाकर महिलाओं को बराबरी के साथ आगे बढ़ाने का स्पष्ट संकल्प दशार्या गया है।
वहीं, बच्चों के बजट (चाइल्ड बजटिंग) के तहत 132 योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत से अधिक, यानी 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि निर्धारित की गई है। मंत्री ने कहा कि यह बजट पूरी तरह समावेशी है, जो महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समाज को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम है झारखंड का बजट : कमलेश

रांची। राज्य सरकार सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बजट राज्य के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट न केवल मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के समाधान की भी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कमलेश ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित और प्रभावी प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं का विस्तार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा। सिंचाई, सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं पर बढ़ा हुआ निवेश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान अत्यंत सराहनीय हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर अवसर मिलेंगे और पलायन की समस्या में कमी आएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में बढ़ोतरी समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीबीआई की दबिश, वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू

बिभा संवाददाता

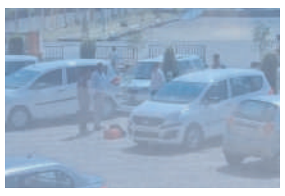

रांची: राजधानी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने छापेमारी की। आधा दर्जन से अधिक वाहनों में आई सीबीआई की टीम ने चेरी मनातू स्थित कैंपस पहुंचकर जांच की प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी जांच का हिस्सा है।
सूत्रों के अनुसार, भवन निर्माण फंड के आवंटन और यूनिवर्सिटी में की गई नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर जांच की जा रही है। सीबीआई अधिकारियों ने पहुंचते ही यूनिवर्सिटी कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और सभी को वहीं रुकने का निर्देश दिया।
टीम ने यूनिवर्सिटी के दूसरे तल पर स्थित वित्त एवं प्रशासनिक शाखा से दर्जनों फाइलें खंगालीं। सीबीआई ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छापेमारी की हो। इससे पहले भी एजेंसी ने यहां वित्तीय लेन-देन और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई की थी।
सीबीआई की अचानक कार्रवाई से यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया। उस समय छात्र अपने-अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खबर फैली, पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बजट में महिला सशक्तिकरण बाल कल्याण पर जोर : विनोद

बिभा संवाददाता

रांची : झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया है।
उन्होंने कहा कि जिस बजट को भाजपा ह्लदिशाहीनह्व और ह्लरंगहीनह्व बता रही है, उसी बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 34,211 करोड़ रुपये का जेंडर बजट, बच्चों के कल्याण हेतु 10,793 करोड़ रुपये का बाल बजट, ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 730 करोड़ रुपये, पर्यटन क्षेत्र में दशम, जोन्हा, हुण्डरू जलप्रपात सहित राज्य के प्रमुख स्थलों के विकास की योजनाएं तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से 1.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं, जो आने वाले समय में लगभग 45 हजार रोजगार सृजित करेंगे।
श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा को महिलाओं, किसानों, युवाओं और गांवों के विकास की योजनाएं लूट इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि यह बजट बिचौलियों के बजाय सीधे आम जनता को सशक्त करता है। धान खरीद, छात्रवृत्ति, पेंशन या गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों पर भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब यही बजट है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को मजबूत किया गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र से प्राप्त सहायता और राज्य के अपने संसाधनों के संतुलित उपयोग से ही विकास संभव है, और यही इस बजट की मूल भावना है। स्थानीय निकायों को पहली बार 1172 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुदान देकर सरकार ने विकेंद्रीकृत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा के पास न तो गांवों के विकास का कोई वैकल्पिक विजन है और न ही महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई ठोस खाका। इसलिए वह जनहितकारी बजट पर तथ्यहीन आरोप लगाकर राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट झारखंड को आत्मनिर्भर और समतामूलक विकास के नए युग में ले जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने की बजट की आलोचना

रांची(बिभा)। झारखंड विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट को लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सरयू राय और जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने बजट को अव्यावहारिक, निराशाजनक और केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित बताया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बजट राशि के प्रभावी उपयोग में विफल रहने का आरोप लगाया है ।मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ष बड़ा बजट पेश करती है, लेकिन उसे समय पर और प्रभावी तरीके से खर्च नहीं कर पाती। कई विभागों में आवंटित राशि लंबित रह जाती है, जिससे विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। मरांडी ने कहा कि राज्य में आज भी लोग सड़क, नाली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी प्रशासनिक कमजोरियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ती है। विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई सोच या ठोस पहल नजर नहीं आती और यह मूल रूप से पिछले बजट की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुराने प्रावधानों को नए शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसमें दूरगामी और प्रभावी योजनाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे बजट की आवश्यकता है, जो वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे और आर्थिक अनुशासन के साथ विकास की स्पष्ट रूपरेखा दे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के विधायक जयराम महतो ने भी बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे कागजों पर लोकलुभावन बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आकर्षक घोषणाएं और बड़ी योजनाएं जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नजर नहीं आता। पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि का स्पष्ट और पारदर्शी ब्योरा तक उपलब्ध नहीं है। जयराम महतो ने सवाल उठाया कि जब पूर्व स्वीकृत योजनाओं का सही आकलन और पारदर्शी हिसाब उपलब्ध नहीं है, तो नई घोषणाओं पर भरोसा कैसे किया जाए। उन्होंने सरकार से पिछले बजट की राशि के खर्च का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो।

मधुबनी कला की साधिका इंदु मिश्रा को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान

रांची (बिभा): भारतीय लोक कला की समृद्ध परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली प्रख्यात मधुबनी कलाकार इंदु मिश्रा को मधुबनी पेंटिंग श्रेणी में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान Adreneur Consultancy Services द्वारा प्रदान किया गया। यह उपलब्धि उनके समर्पण, साधना और भारतीय लोक कला के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। इस अवसर पर इंदु मिश्रा ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए विनम्रता और गर्व का क्षण है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, बच्चों, मित्रों एवं शुभचिंतकों के निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन को दिया। उन्होंने कहा, कला भले ही एक एकाकी यात्रा प्रतीत होती हो, पर मैंने यह सफर कभी अकेले तय नहीं किया। मेरी हर कूची की रेखा के पीछे मेरे अपनों का प्रेम और विश्वास है। विशेष रूप से उन्होंने यह सम्मान पूर्व क्रिकेट दिग्गज चेतन शर्मा के हाथों प्राप्त करने को गौरवपूर्ण क्षण बताया, जिन्होंने विश्व कप में भारत की पहली हैट्रिक लेकर इतिहास रचा था। इंदु मिश्रा की कला यात्रा वर्ष 2013 में एक स्वाभाविक रुचि के साथ शुरू हुई। स्वशिक्षित कलाकार के रूप में उन्होंने मधुबनी की पारंपरिक शैली को आत्मसात करते हुए उसे आधुनिक संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित उनकी कलाकृतियां सूक्ष्म रेखांकन, लयात्मक संरचना, प्रतीकात्मक कथात्मकता और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती हैं।

आरपीएफ रांची ने अवैध शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार

रांची (बिभा): रांची मण्डल मे मण्डल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ बेहद सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है उसी क्रम मे 22 फरवरी को आरपीएफ पोस्ट रांची की ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी द्वारा ट्रेन संख्या 18622 (हटिया से बोकारो स्टील सिटी) में ड्यूटी के दौरान ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत सघन जांच की गई। टाटीसिलवे स्टेशन के समीप बी-1 कोच के विभिन्न बर्थों से संदिग्ध ट्रॉली बैगों की जांच के दौरान कुल 55 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कुल अनुमानित कीमत लगभग 46,000/- है। जांच के क्रम में तीन व्यक्तियों पुष्कर सिंह (उम्र 18 वर्ष), चंदन सिंह (उम्र 19 वर्ष) एवं रौनक कुमार सिंह (उम्र 18 वर्ष), सभी जिला भोजपुर (बिहार) के निवासी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे रांची से शराब खरीदकर बिहार में अधिक मूल्य पर बेचने हेतु ले जा रहे थे। उक्त अवैध शराब को जब्त कर आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 23 फरवरी को अगली कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग, रांची को सुपुर्द कर दिया गया। यह कार्रवाई उपनिरीक्षक सचिन कुमार, प्रधान आरक्षी जागेश्वर कुमार, कांस्टेबल सोनू कुमार एवं कांस्टेबल गोपी कृष्ण की टीम द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

झारखंड विधानसभा में पेश किया गया राज्य सरकार का बजट दिशाहीन एवं तथ्यहीन : आदित्य साहू

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए गए बजट को दिशाहीन और तथ्यहीन करार दिया है।
रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट केवल गोलमटोल आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण है, जिसमें राज्य के विकास का कोई स्पष्ट विजन नजर नहीं आता। उन्होंने इसे ह्लरंगहीन और खुशबू विहीनह्व बजट बताया।
आदित्य साहू ने कहा कि बजट भाषण के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वित्त मंत्री आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भी एक बार मेज थपथपाकर उनका उत्साहवर्धन नहीं किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री पहले स्वयं कह चुके हैं कि उन्हें बजट की जानकारी नहीं दी गई, जबकि अब उसे आदर्श बजट बताया जा रहा है। साहू ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया की बात बार-बार करती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करती कि यह राशि कब और किस मद में बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उठा रही है।
आदित्य साहू ने कहा कि सरकार बजट को बाल बजट बता रही है, लेकिन राज्य के हजारों लापता बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने जैसी गंभीर घटनाओं पर भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जेंडर बजट की बात तो की जा रही है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती।
आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन 2450 रुपये भी किसानों तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि बिचौलियों ने इसका लाभ उठा लिया। इसके अलावा 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का भी बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार पैसों की कमी न होने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर घोषणाओं को लागू करने में पूरी तरह विफल रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, एयरपोर्ट क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित

बिभा संवाददाता

रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। उनके आगमन और प्रस्थान को देखते हुए राजधानी रांची में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रांची पहुंचने के बाद जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पूरी परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित सभी प्रकार के मानवरहित या हल्के विमानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला जनसम्पर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी को सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। आदेश के तहत एयरपोर्ट क्षेत्र और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित गतिविधि से दूर रहें, जिससे कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

होली के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण 9 खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने लगाया जुर्माना

बिभा संवाददाता

रांची : आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को रांची रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित कुल 15 खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य पर्व के दौरान लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था।
निरीक्षण के दौरान कुलदीप होटल, होटल एम्बेसडर, होटल कृष्ण, लवली डेयरी, अन्नपूर्णा भोजनालय, आर.के. भोजनालय, होटल मानसरोवर, होटल मां डेयरी, तंदूर फूड वैन, एम्बसी फूड प्लाजा, सन्नी रेस्टोरेंट, शिवम खाजा भंडार, कुशवाहा खाजा भंडार, पंजाबी बार एंड रेस्टोरेंट तथा खालसा रेसिडेंसी का निरीक्षण किया गया।
जांच के क्रम में जिन निबंधित दुकानों में कमियां पाई गईं, उन्हें सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। साथ ही, 9 खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुमार्ने की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण दल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भविष्य में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पर्व-त्योहार के अवसर पर आम नागरिकों एवं यात्रियों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बजट में झारखंड के विकास की दिशा में हुई है सकारात्मक पहल : चेंबर

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड बजट 2026-27 पर चेंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए बजट आवंटन को और बढ़ाने की आवश्यकता थी।
आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन संभव है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और कौशल विकास पर दिया गया जोर सराहनीय है, लेकिन उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश, ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और क्लस्टर विकास के लिए अधिक प्रावधान अपेक्षित थे। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और खनिज आधारित उद्योगों के लिए समर्पित प्रोत्साहन पैकेज से निवेश को गति मिल सकती थी।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया पर और ठोस पहल जरूरी है। लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की दिशा में भी बजट में अधिक स्पष्टता होनी चाहिए थी।
मल्होत्रा ने कहा कि व्यापार के दृष्टिकोण से जीएसटी अनुपालन में सरलीकरण, निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार भी जरूरी है। निर्यात प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स को बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष नीति राज्य के व्यापार को नई ऊंचाई दे सकती है।
कुल मिलाकर बजट संतुलित है, लेकिन उद्योग और व्यापार की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक व्यवस्था और लक्ष्य आधारित प्रावधान किए जाने चाहिए थे।

पूर्व मध्य रेल
ई–निविदा नोटिस
सं0–डी.डी.यू/ईएल/जी/ई0–निविदा/2025–26/27
मंडल रेल प्रबन्धक/विद्युत/जी/डी.डी.यू एवं भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से अनुभवी तथा वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से सम्पन्न ठेकेदारों के साथ–साथ उन ठेकेदारों से जो रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों मे सूची बद्ध है, निम्न लिखित कार्य के लिए ऑनलाईन (ई.–निविदा) आमंत्रित की जाती हैं। (1) **कार्य क्षेत्र के साथ कार्य का नाम:** डी.डी/यू/ईएल/जी/पी/2025–26/13 आर **विषय.**– डीडीयू मंडल के डीडीयू के टीएस–1 और एचटी सेक्शन के अंतर्गत आपात कालीन प्रकाश सहित रोशनी में सुधार सहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली का उन्नयन में विद्युती कार्य करने के संबंध में। **कार्य करने की कुल लागत:** रू0 18281185.69, **निविदा बंद करने की अंतिम तिथि एवं समय:** रू0 17.03.2026 15:00 बजे, **ई–निविदा वेवसाइट का विवरण:** www.ireps.gov.in
वरिष्ठ मंडल विधुत अभियंता (सा0)
पूर्व मध्य रेल, डी.डी.यू
पीआर/1836/डीडीयू/ईएलईसीटी/टी/25–26/28

पूर्व मध्य रेल
ई–निविदा नोटिस
सं0–62 ऑफ 2025–26/खुला/इंजीनियरिंग, डीडीयू
मंडल रेल प्रबन्धक/इंजीनियरिंग/डीडीयू एवं भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से अनुभवी तथा वित्तीय एवं तकनीकि दृष्टि से सम्पन्न ठेकेदारों के साथ–साथ उन ठेकेदारों से जो रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगभ लिमिटेड, मिलिटरी इंजीनियर सर्विस, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित कार्य के लिए ऑन लाईन (ई–निविदा) आमंत्रित की जाती हैं। (1) **कार्य का नाम एवं लोकेशन: निविदा सं0–03–डीडीयू–व0मं0इंजी0–सी–25–26** नबीनगर रोड साइडिंग के लिए बीजी रेलवे ट्रैक के लिए नवीनतम सुधार पर्चियों सहित ट्रैक गिट्टी, आइ0एस0/आर0डी0एस0ओ0जीई/0001:2023, फरवरी 2023 के लिए आर0डी0एस0ओ0 के विनिर्देषों की पुष्टि करने वाली 60000 धन मी0 50 मिमी आकार की मशीन क्रस्ड ट्रैक गिट्टी की आपूर्ति और स्टैकिंग और इसे बोबीएन /ओपन वैगन में लोड करना। **(2) कार्य का अनुमानित लागत:** रू0119647200.00 **(3) धरोहर राशि:** रू0 748200.00 **(4) ई–निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय :** 17.03.2026 को 12:00 बजे तक **(5) बेवसाइट पर ई निविदा की विस्तृत जानकारी:** www.ireps.gov.in, **नोट:**– विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
मंडल रेल प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, पं0 दीन दयाल उपाध्याय
पीआर/1837/डीडीयू/ईएनजीजी/टी/25–26/32

बिहान भारत
www. bihanbharat.org

email. : bihanbharatranchinews@gmail.com
रांची, बुधवार
25 फरवरी 2026

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं।

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मयार्दा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दशार्ता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

संपादकीय

शंकराचार्य बनाम साधु

तिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप अश्लील हैं कि उन्होंने और उनके शिष्य ने दो नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया। जो आशुतोष ब्रह्मचारी नामक कथित साधु ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, वह भी एक और संन्यासी, कथित जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जा रहा है। अदालत में जज के सामने धारा 164 के तहत नाबालिग शोषितों के बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। पॉक्सो की विशेष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। चूंकि मामला पॉक्सो का है, लिहाजा बेहद संवेदनशील है। क्या शंकराचार्य को जेल भी भेजा जा सकता है? यदि ऐसा हुआ, तो बड़ा धार्मिक वज्रपात होगा, क्योंकि शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सनातन के शिखर-पुरुष हैं, सर्वोच्च धर्मगुरुओं में शामिल हैं। जिस साधु-संत के असंख्य श्रद्धालु हैं, उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें ह्यभगवानह्न मान कर प्रणाम करते हैं, एक और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, शंकराचार्य के ही, बटुकों की शिखा खींचने को ह्यमहापापह्न करार देते हैं और अपने आवास पर बटुकों का सम्मान करते हैं, उसी शख्स के शंकराचार्य होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। आश्चर्य है कि उप्र में यह क्या हो रहा है? हिंदुत्व और सनातन की कट्टर समर्थक, पैरोकार भाजपा की सरकार में सनातन-पुरुष पर ही घमासान क्यों मचा है?

जो अभी तक शंकराचार्य हैं, जिनके पदनाम पर सर्वोच्च अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जो शंकराचार्य सनातन के शिखर संतों में एक हैं और आदि शंकराचार्य की प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें ही दुराचारी और बलात्कारी करार क्यों दिया जा रहा है? इन आरोपों की तुलना आसाराम बापू के केस से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बलात्कार की निरंतर पीड़िता नाबालिग कन्या के परिजनों ने भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। मीडिया के सामने आकर दुष्कर्म-कथा सुनाई थी। आसाराम को ह्यभगवानह्न मानने वालों की भी कमी नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उनके ह्यभक्तह्न थे। मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की आस्था, श्रद्धा भी उनके प्रति थी। आसाराम कई सालों से जेल में हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

चिंतन-मनन

कहीं आप भी पाप की पूंजी तो जमा नहीं कर रहे

क्या आपने कभी किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठायी है। किसी कमजोर और लाचार को पिटता देखकर मदद के लिए आगे आएं हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो समझ लीजिए आपने अपने खाते में पाप की पूंजी जमा कर ली है। जिस प्रकार से पाप और पुण्य को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार जो व्यक्ति किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद नहीं करता है। किसी के भय से अथवा अपने स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है और शरण में आये व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है वह पापी है।

इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। एक थे राजा शिवि। इनके धार्मिक स्वभाव और दयालुता एवं परोपकार के गुण की ख्याति स्वर्ग में भी पहुंच गयी। इन्द्र और अग्नि देव ने योजना बनायी कि राशि शिवि के गुणों को परखा जाए। एक दिन अग्नि देव कबूतर बने और इन्द्र बाज। कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवि की गोद में आकर बैठ गया और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी बीज बड़ा सा बाज राजा शिवि के पास पहुंचा और कबूतर को वापस करने के मांग करने लगा। बाज ने कहा कि, कबूतर मेरा आहार है अगर आप मुझे वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा।

बाज की बातों को सुनकर राजा शिवि ने कहा कि कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा अगर कोई अन्य उपाय है तो बताओ। बाज ने कहा कि कबूतर के मांस के बराबर मुझे मांस दे दीजिए इससे मेरा काम हो जाएगा। राजा ने विचार किया कि एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव का कष्ट देना पाप होगा। यही सोच कर राजा ने कबूतर को तराजू के एक पलडे में डाल दिया और अपने शरीर से मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखने लगे। लेकिन काफी मांस रखने के बाद भी पलड़ा हिला तक नहीं। अंत में राजा शिव स्वयं दूसरे पलड़े पर बैठ गये और बाज से कहा कि तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। राजा के इस दयालुता और शरण में आये हुए कि मदद करने की भावना को देखकर कबूतर अग्नि देव और बाज देवराज इन्द्र के रूप में प्रकट हुए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवराज इन्द्र ने कहा कि तुम ने धर्म की लाज रखी है। जो शरण में आये की रक्षा नहीं करता वह पापी है। कमजोर की सहायता न करने वाला भी अधर्मी है। दोनों देवताओं ने राजा शिवि को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग चले गये।

कार्टेल के खिलाफ जंग और मेक्सिको की अग्निपरीक्षा

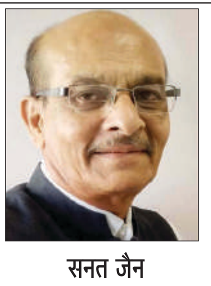

सनत जैन

मेक्सिको में कुख्यात ड्रग सरगना नेमेंसियो ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ 'एल मेंचो' के मारे जाने की खबर के बाद हुई भारी हिंसा से मेक्सिको को अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई है। नशे के कारोबार में (सीजेएनजी) प्रमुख के रूप में ड्रग लॉर्ड को न केवल मेंक्सिको, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। मेक्सिको की सरकार इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। किंतु ड्रग सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद भड़की आगजनी, हाईवे जाम और सुरक्षा कर्मियों पर हमले से यह सवाल उठता है, क्या किसी सरगना के मारे जाने पर जनता का विद्रोह इस रूप में देखने को मिल सकता है? एल मेंचो पर अमेंरिका की सरकार ने बड़ा इनाम घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल से ही मेक्सिको पर ड्रग तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दबाव अमेंरिका की सरकार बनाती रही है। फेंटानिल संकट ने अमेंरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, इसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना तय है। मेक्सिको की हिंसा केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका असर अमेंरिका सहित अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। यह घटना भू-राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी दिखती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह मेक्सिको की संप्रभु रणनीति का हिस्सा है, या अमेंरिकी दबाव का परिणाम है। इतिहास बताता है कि कार्टेल के शीर्ष नेता को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होता है। इससे ड्रग के कारोबार, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में स्थिरता संभव नहीं है। 2016 में जोक्विन एल चापो गुजमान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आम जनता और सत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा था। संगठित अपराध का नेटवर्क समानांतर व्यवस्था की तरह संचालित होता है। एक चेहरा हटता है, तो उसके कई दावेदार उभरते हैं। गैंग में वर्चस्व की लड़ाई आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। एल मेंचो की मौत के बाद इस तरह की घटनाएं इसी आशंका को पुष्ट कर रही हैं। ड्रग कारोबार और राजनीतिक संरक्षण का मूल मेक्सिको, अमेंरिका एवं कई अन्य देशों तक फैला हुआ है। दशकों से मेक्सिको में फैली गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और कमजोर तथा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से जुड़ता है। मेक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पकड़ हमेंशा से कमजोर रही है। नशे के कारोबारी और इससे जुड़े हुए लोगों की समानांतर सत्ता चलती है। नशे के कारोबार में लगे अपराधी तत्व जिस तरह से काम करते हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों को वसूली के डर से नियंत्रण और सीमापार तस्करी इनके साधन हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है। मेक्सिको सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक ओर सरकार के ऊपर तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल कर नागरिकों में भरोसा कायम करना है, दूसरी ओर दीर्घकालिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

मेक्सिको में न्यायिक पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा, नशे की कारोबार में नेटवर्क पर वित्तीय प्रहार और पुलिस सुधार अनिवार्य है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के बीच का भ्रष्टाचार रोकना, संस्थागत ढांचे को मजबूत नहीं किया तो यह 'जीत' अस्थायी साबित होगी। इसके साथ ही, इसका असर अमेंरिका में भी पड़ना तय है। अमेंरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक अमेंरिका में नशीली दवाओं की मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के नए रास्ते और नए गिरोह समय-समय पर उभरते रहेंगे। नशे का कारोबार केवल मेक्सिको की समस्या नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साझा जिम्मेंदारी जरूरी है। दबाव की नीति के बजाय सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। एल मेंचो का अंत

प्रतीकात्मक जीत हो सकती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि मेक्सिको में सुशासन और पारदर्शिता चाहिए तो भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक निवेश की ठोस रणनीति बनानी होगी। तभी नशे के कारोबार के गैंगस्टरों की छाया से मेक्सिको बाहर निकल पाएगा। इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता है। नशे के कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसमें भारी पैसा है। इस नेटवर्क को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के पश्चात जिस तरह के हालात मेक्सिको के बन गए हैं, उस चुनौती से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका इस मामले में मेक्सिको की क्या मदद करता है, यह भी देखना होगा।

कचरे पर कड़ा रुख: न्यायपालिका के निर्देश और जमीनी सच्चाई

सुनील कुमार महला

ठोस कचरे का प्रबंधन आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि आज लगातार बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण, औधोगिकीकरण और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण धरती पर ठोस कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव व जीवों के स्वास्थ्य और विभिन्न संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस कचरे का सही तरीके से संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) और इसका समय रहते निपटान नहीं किया गया, तो नीले ग्रह(धरती पर) पर भूमि, जल और वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

वास्तव में, आज के समय में ठोस कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करना, जैविक कचरे से खाद बनाना, प्लास्टिक और अन्य पदार्थों का पुनर्चक्रण(रि-साइक्लिंग) करना तथा जन-जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे, तभी सतत विकास(सस्टेनेबल डेवलपमेंट) और स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस क्रम में

हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के ठीक से पालन न होने पर चिंता जताई है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना, जीवन के अधिकार का ही अहम् हिस्सा है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने 19 फरवरी को यह आदेश सुनाया। दरअसल, यह मामला भोपाल नगर निगम की उन अपीलों से जुड़ा था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं।

अदालत ने यह बात कही है कि अभी कानून में सुधार का इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कचरे की खराब व्यवस्था से लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में कचरा प्रबंधन नियमों का पालन समान रूप से नहीं हो रहा है और घरों से गीला-सूखा-खतरनाक कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। बड़े शहरों में बढ़ते कचरे के ढेर भी चिंता का कारण हैं।कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा अब नहीं तो कभी नहीं और स्पष्ट किया कि अगर स्रोत पर कचरा अलग नहीं होगा और जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों और वार्ड प्रतिनिधियों को कचरा अलग कराने के लिए जिम्मेदार लीड फैसिलिटेटर बनाने को कहा, ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे। यहां पाठकों को बताता चलूं कि लीड फैसिलिटेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यशाला या परियोजना में पूरे समूह की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ सही दिशा में और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार चलें। अच्छी बात यह है कि सभी नगर निकायों को 100% पालन के लिए समय-सीमा तय कर सार्वजनिक करने, प्रगति की फोटो जिलाधिकारी को भेजने और बड़े कचरा उत्पादकों से 31 मार्च तक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार तरह के कचरे (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष) के अलग-अलग प्रबंधन की व्यवस्था जल्दी तैयार करने को कहा गया है।

अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन नियमों को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया जाए और इन्हें सभी राज्यों की स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए।अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले जुमार्ना, बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। कोर्ट ने मोबाइल अदालतों की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी न्यायालयों और संस्थानों में भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निकायों को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने होंगे, जैसे कचरा कम करना, घर में खाद बनाना और सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से पैक करना।ये सभी निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल 2026 से पहले पूरी तैयारी हो सके और नियम सही तरीके से लागू किए जा सकें।

अंत में यही कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही चिंता जताई है कि ठोस कचरा प्रबंधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नियमों के कमजोर अनुपालन, स्थानीय निकायों की जवाबदेही की कमी और योजनाओं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज मिशन में खामियों के कारण समस्या बढ़ी है। समाधान के लिए सख्त नियम लागू करना, जनजागरण, अधिकारियों की जवाबदेही और बेहतर शहरी अवसंरचना निवेश अनिवार्य हैं, तभी कचरा-मुक्त भारत का लक्ष्य संभव हो पाएगा।

अब अपनी हॉबी को ही बना सकते हैं करियर ऑप्शन

आज के समय में जॉब करना आसान नहीं रह गया है। यह काम तब और मुश्किल हो जाता है, जब किसी का प्रोफेशन और हॉबी अलग-अलग हो। जिसके कारण आजकल कई लोग जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वे उन जॉब्स से खुश नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए जॉब करना और अपने पैशन को फॉलो करके उसमें आगे जाना दोनों बहुत अलग बात हैं। फिर चाहे उसमे पैसे थोड़े कम क्यों न हो।

फोटोग्राफी, राइटिंग, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग समेत कई ऐसी हॉबी होती हैं, जिन्हे आप फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। सोचिये जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपकी हॉबी है, उसे आप अलग से समय निकाल कर करते हैं, अगर इसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आप भी अपनी हॉबी को करियर का रूप देना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए 7 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले रिसर्च करें

अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है रिसर्च। किसी भी हॉबी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता लगाना है कि क्या आपकी हॉबी फुल टाइम करियर बना सकती है या नहीं। उसमें जॉब और करियर के क्या अवसर हैं और उस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनुभव की जरूरत पड़ती है।

सही फीडबैक लें

कोई भी व्यक्ति अपने काम को जज नहीं कर सकता और न ही आपका परिवार या दोस्त आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गाइडेंस के लिए जरूरत होती है एक अनुभवी प्रोफेशनल की जो आपका मेंटर बने। हमेशा याद रखें कि काम शुरू करने से पहले अपनी हॉबी के बारे में अपने मेंटर से ईमानदार फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूलें।

शुरू से शुरुआत करें

यह बात पहले ही अपने मन में बैठा लें कि जब आप कोई करियर स्विच करेंगे तो हो सकता है कि आपको नीचे से ही शुरू करना पड़े। आप अपनी जॉब में फिलहाल ऊंची पोस्ट पर हों, लेकिन आपको नये करियर में नीचे से ही शुरू करना होगा। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लें।

पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल

आपके पुराने और नये करियर में भले ही कोई समानताएं न हों। लेकिन फिर भी हर जगह से हम कुछ न कुछ स्किल्स तो सीखने को मिलती ही हैं। ऐसी कई स्किल होती हैं, जो हर फील्ड में काम आती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल यहां भी काम आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सभी स्किल का इस्तेमाल अपने नये करियर में करें।

अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनें

अपनी हॉबी में करियर बनाने से पहले आप उस फील्ड से जुड़े लोगों से संपर्क बनाएं। अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं, एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको उस फील्ड में सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अपने काम को मोनेटाइज करें

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक बिजनेस टर्म है जिसका इस्तेमाल उन उद्यमियों के द्वारा किया जाता है जो फंडिंग की तलाश में होते हैं। आपको भी अपने लिए फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए आर्थिक सुविधा बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं रहेगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश करें। आप चाहे तो आपकी स्किल को ऑनलाइन सिखा सकते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर ले सकते हैं। या फिर खुद की वर्कशॉप भी लगा सकते हैं।

इस तरह बदले अपने पैशन को प्रोफेशन में

जब आपके मन में अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का विचार आए तो सबसे पहले अपने सभी हॉबी की लिस्ट बनाएं। मान लीजिये आपकी तीन हॉबी हैं। आपको लिखने का शौक हैं, फोटोग्राफी और पेंटिंग का भी शौक है। अब एक-एक हॉबी पर विचार कीजिए और उसके साथ कुछ दिन जी कर देखें। इससे आपको अपने आप ही मालूम हो जायेगा कि किस काम को लेकर आप ज्यादा बेहतर हैं और वह कार्य करते हुए आपको ज्यादा खुशी मिलती है।

सफलता के लिए हमेशा याद रखें...

किसी भी कार्य की सफलता के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए। कार्य को प्रारम्भ करने के पीछे हमारा भाव क्या है। हम क्या करना चाहते हैं इसका महत्व है। सफलता के लिए भगवान का सुमिरन कर कार्य करें। भगवान का ध्यान कर किए जाने वाले कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता। कुछ लोग भगवान की असीम कृपा से कम परिश्रम में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। संतों ने सफलता के 3 मंत्र बताए। पहला भगवान का स्मरण, दूसरा धैर्य तथा तीसरा परमार्थ की भावना जुड़ी होनी चाहिए।

प्रत्येक मंदिर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए और भीतर से पवित्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भी बाहर से स्वच्छ और भीतर से पवित्र होना चाहिए। फिर कोई लम्बी साधना करने की जरूरत नहीं। मां त्रिस्तरीय काम करती है। सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका परिपालन और उसका संघार करती है। अम्बा के 3 स्तर हैं, स्त्री शरीर अम्बा का ही अंश है। ऐसा मानकर उसका 3 स्तर पर सम्मान करना चाहिए। कन्या का सम्मान, धर्मपत्नी का सम्मान और मां का सम्मान। आनंद की अंतिम सीमा आंसू हैं। हम सबका जीवन फल होना चाहिए प्रेम। सत्य शायद हम चूक जाएं। करुणा छूट जाए लेकिन प्रेम बना रहे। यह जीवन का फल है।

स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर

यदि आप लेखन में दक्षता रखते हैं और आपको किताबें पढ़ने में भी गहरी रुचि है तो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप अपने शौक को करियर का रूप भी दे सकते हैं। जो युवा लिखने-पढ़ने के साथ मानवीय संवेदनाओं को पकड़ कर अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्षेत्र

विज्ञापनों के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स की सेवाएं विशेष तौर पर ली जाती हैं। अक्सर विज्ञापनों में ऐसे शब्दों या पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। ये सब स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग की ही उपज होते हैं। ऐसी रोचक बातों को जिंगल्स कहा जाता है।

बेशक स्क्रिप्ट राइटर का काम सिर्फ जिंगल लिखना ही नहीं होता बल्कि और कई चीजें हैं जो स्क्रिप्ट राइटर करते हैं लेकिन अधिकतर की शुरूआत जिंगल्स से ही होती है।

जाहिर है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कहानियां और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है इसीलिए लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं देखी जाएगी।

कौशल

इसमें क्षेत्र में करियर बनाने के लिए छात्रों में रचनात्मकता का होना आवश्यक है। कम शब्दों में आपको उत्पादों की विशेषताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। विज्ञापनों के लिए ऐसी जिंगल्स की रचना करनी पड़ती है कि सुनते या पढ़ते ही वह ग्राहक के जेहन में आ जाए। वैसे कोई डिग्री कोर्स तो नहीं होता पर ये जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है।

कल तक विज्ञापन ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बनाए जाते थे लेकिन आज जो विज्ञापन आ रहे हैं वे ग्राहकों के संतोष के साथ उसकी खुशी और मनोरंजन को भी महत्व दे रहे हैं। मानवीय भावनात्मक पक्षों को छूते विज्ञापन न सिर्फ देर तक याद रहते हैं बल्कि मन पर भी गहरा असर छोड़ते हैं।

जिस भी भाषा में आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं उसका गहन ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको विभिन्न लेखकों की शैली की जानकारी भी प्राप्त हो सके। साथ ही फिल्मों तथा धारावाहिकों की स्क्रिप्ट पर गौर करने की आदत भी डाल लें। इसके बाद आप स्क्रिप्ट लेखन में हाथ आजमाएं।

योग्यता

स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे अहम जरूरत रचनात्मकता की होती है जो पूर्णत- व्यक्ति की विश्लेषण और कल्पना क्षमता पर आधारित होती है लेकिन फिर भी इसके लिए पत्रकारिता का कोर्स कर लिया जाए तो बेहतर होता है। किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास करने के बाद पत्रकारिता में ग्रैजुएशन कर सकते हैं। जो छात्र ग्रैजुएशन कर चुके हैं वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता में एम.ए. भी कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
एमिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
इंडियन इंस्टी. आफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

लाभदायक करियर इमेज कंसल्टिंग

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरेंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के ढंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टैंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमैंट, पॉलिसी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनैस इंस्टी. भारत में इमेज कंसल्टैंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनैस प्रोग्राम संबंधी अनोखे पेशेवर कोर्स करवाता है। इस संस्थान की डायरैक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टैंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान की डायरैक्टर हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2009 में की। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफैशनल इंटरनैशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टैंट बन गई। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, ''80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कौशल एक इमेज कंसल्टैंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।'' उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

पत्राचार शिक्षा से बदलती युवाओं की तकदीर

आज सभी विषयों में ग्रैजुएशन तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टीफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है। अधिकतर पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें सभी विषय-विधाओं के 10+2 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। उपग्रह संचार, लो पावर ट्रांसमीटर्स की सहायता एवं सूचना सुपर-हाइवेज के माध्यम से देश भर में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, सेवारत व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं।

अधिकांश विश्वविद्यालय मुद्रित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।

बंगाल के एसआईआर में लाखों दावों-आपत्तियों से निपटेंगे झारखंड-ओडिशा के जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर में 80 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए सिविल जजों को नियुक्त करने और पड़ोसी राज्यों झारखंड व ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर कवायद के लिए तैनात 250 जिला न्यायाधीशों को दावों और आपत्तियों से निपटने में करीब 80 दिन लगेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर स्थिति और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए पीठ ने प्रक्रिया संचालित करने के लिए सिविल जजों की तैनाती की अनुमति दी। उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से झारखंड और ओडिशा के अपने समकक्षों से

अनुरोध करने और स्थिति से निपटने के लिए समान पदों के न्यायिक अधिकारियों की मांग करने को कहा। पीठ ने निर्वाचन आयोग को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का खर्च वहन करने का निर्देश भी दिया। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति भी दी और स्पष्ट किया कि सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ने पर चुनाव आयोग पूरक सूचियां जारी कर सकता है। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से पारिवारिक संबंध जोड़ने में तार्किक विसंगतियों में ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें माता-पिता के नाम में असंगति पाई गई है और मतदाता व उसके माता-पिता के बीच आयु का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच गतिरोध से निराश होकर राज्य में विवादों से घिरे एसआईआर में आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों को तैनात करने का एक निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग और बंगाल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई टीएमसी सरकार के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप और विश्वास की कमी पर अफसोस जताते हुए पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश पारित किए थे।

गुटखे के प्रचार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी बनाया पक्षकार

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अपने पूर्व के आदेश के पालन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्राधिकरण से पूछा था कि 2023 में याची के प्रत्यावेदन पर अब तक जांच लंबित क्यों है? याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खां व रणवीर सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं उनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं और उनकी ओर से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी है।

दर्दनाक हादसा–घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के छह लोग जिंदा जले, महिला घायल

मेरठ (एजेंसी)। यूपी के मेरठ जिले में एक मकान में आग लगने से पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मंगलवार को यहां बताया कि घटना किदवई नगर इलाके में बीती रात करीब आठ बजे हुई। उन्होंने बताया कि इकबाल अहमद के आवास पर आग लगने की सूचना रात आठ बजकर 49 मिनट पर मिली, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि तीन मिनट के भीतर, डायल 112 पुलिस प्रतिक्रिया वाहन मौके पर पहुंच गया और उसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। पुलिस के मुताबिक, घर में सिलाई का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। उन्होंने कहा कि इलाके में संकरी गलियों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में चुनौती पेश आती है इसीलिए अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल की गईं नयी मोटरसाइकिलों को भेजा गया। एसएसपी ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने भी फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए सीढ़ी लगाकर बचाव प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है और विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में सात लोग झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चिकित्सकों ने उनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रुखसार (25), महबीश (12), हम्माद (चार), अकदस (चार), नबिया (चार माह) और इनायत (चार माह) के रूप में की गई है, जो किदवई नगर में सुराही वाली मस्जिद के पास गली नंबर तीन के निवासी थे। एसएसपी ने बताया कि घायल महिला अमीर बानो (55) का उपचार किया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य मोहम्मद फारूक ने कहा कि जब उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो वह नमाज पढ़ने गए थे।

नीतिश के मंत्री का राहुल गांधी पर हमला, देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती

पटना (एजेंसी)। बिहार में नीतिश सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती। राहुल गांधी की पहचान अब इसतरह के नेता के तौर पर है जो देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा हैं, लेकिन राहुल गांधी को सफलता हाथ नहीं लग रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस विरोध पर नीतिश सरकार में मंत्री पांडे ने कहा कि जब भी भारत को बदनाम करने या देश की इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस सबसे आगे रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजी से मजाक का विषय बनते जा रहे हैं। इसकारण भारत की जनता राहुल गांधी को कभी गंभीरता से नहीं लेती। मंत्री पांडे ने कहा कि एआई समिट विश्व का मंच था, जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वहां जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वह निंदनीय है। कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से सभी को बहुत आघात पहुंचा है। कांग्रेस के लोग पता नहीं कि अब लोकतंत्र में क्या दिखाना क्या चाहती है। कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट से देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कहा कि आपने देखा कि एआई समिट में 140 देशों के प्रतिनिधियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था और किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक छोटी–सी बात को लेकर भारत की छवि को दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश की गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने पर 13 छात्रों को नोटिस

लखनऊ (एजेंसी)। रमजान के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के प्रकरण में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर 13 छात्रों को नोटिस दे दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महानगर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत जारी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लाल बारादरी के पास चल रहे निर्माण कार्य को बाधित करने का काम किया। कैंटीन के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि इन गतिविधियों से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को निर्देश दिया है कि वे एक वर्ष तक शांति और कानून–व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में 50 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और 50–50 हजार के दो जमानतदार प्रस्तुत करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बारादरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिंदू छात्रों ने चेन बनाकर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में मदद की थी। सोमवार को छात्रों के दूसरे संगठन ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि लाल बारादरी में रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके बावजूद छात्र यहां नमाज अदा करने पहुंचे थे। जब छात्रों को नमाज पढ़ने से रोका गया तब हिंदू छात्रों ने बैरिकेटिंग को गिरा दिया और ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद छात्रों ने नमाज अदा की और रोजा खोला।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा के साथ महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक महिला यात्री को अवैध रूप से महंगे आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अमेरिकी पासपोर्ट धारक यह महिला हांगकांग से फ्लाइट नंबर सीएएक्स–695 द्वारा टर्मिनल–3 पर पहुंची थी। महिला पर संदेह होने पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें रोका और सामान की एक्स–रे जांच की। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत विस्तृत तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अघोषित विदेशी सामान बरामद हुआ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके: अनुराग ठाकुर

कांगड़ा (एजेंसी)। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन चुके हैं। कांगड़ा में भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बने हुए हैं। वह भारत में रहकर और भारत के बाहर रहकर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, इतना ही नहीं नकारात्मक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। अब उनका एकमात्र काम झूठ बोलना, कन्फ्यूजन पैदा करना, भारत को बदनाम करना और मोदी विरोधी राजनीति करना है। जब भारत की इकॉनमी सबसे तेजी से बढ़ रही है, तब वह भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहते हैं। उन्हें भारत की तरक्की पसंद नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया ने एआई समिट की तारीफ की, वहां राहुल गांधी के इशारे पर उनके कार्यकर्ता शर्टलेस प्रदर्शन कर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी की राजनीति विदेशों से तय हो रही है। कांग्रेसी विदेशियों का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जॉर्ज

सोरेस के कहने पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा ले रही है और फिर चीन का गुणगान कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुडदंग, ल से लंफगई। उनकी जगहंसाई हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सच में नेता प्रतिपक्ष हैं।

भाजपा सांसद ने कहा कि संसद में महिला सांसदों को भेजकर पीएम की सीट का घेराव करना किस तरह की राजनीति है। विदेशी मंचों पर जाकर राहुल गांधी बयान देते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, उनका यही काम रह गया है। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जो सोच रहे हैं, वह सफल नहीं हो सकते है।

कांग्रेस डरपोक नहीं, संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि वे हमारे युवा नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस न तो डरपोक है और न ही डरने वाली है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो नितिन गडकरी और बीजेपी नेताओं ने क्या किया? ऐसे हर इवेंट में वे देश की भावना को समझने में नाकाम रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे उस समय भारत और विदेश के एथलीटों को क्या संदेश जाएगा। बीजेपी दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। अगर वे अपने गिरेबान में झांकेंगे, तो शायद उन्हें अपनी सच्चाई दिखाई देगी। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष

भानु की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।

रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश का माहौल इतना खराब हो चुका है कि उसके कारण केंद्र सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। मैं चाहता था कि पीएम मोदी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार वह कर रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का नुकसान होगा। हमें बंधुआ मजदूर बनाने की दिशा में धकेला जा रहा है।

खड़गे ने कहा कि सरकार की ओर से कांग्रेस को डराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न ही डरपोक है। हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि प्रदर्शन करने के बाद अगर हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस कुछ देर बाद छोड़ देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को निशाना बनाकर डर पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस डरने वाली नहीं है।

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर थरुर का मजाकिया अंदाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने एक दिलचस्प लेकिन अहम भाषाई सवाल उठा दिया है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरुर ने अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर कहा कि नाम परिवर्तन सभी के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए एक छोटा सा भाषाई प्रश्न खड़ा होता है। उन्होंने हल्के–फुल्के अंदाज़ में पूछा कि अगर राज्य का नाम 'केरलम' हो जाएगा, तब वहां के निवासियों को क्या कहा जाएगा....केरलाइट', 'केरलन' या कुछ और?

कांग्रेस सांसद थरुर ने मजाकिया लहजे में लिखा कि 'केरलमाइट' शब्द सुनने में किसी सूक्ष्म जीव (माइक्रोब) जैसा लगता है, जबकि 'केरलमियन' किसी दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मटीरियल) की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने केरल के सीएम ऑफिस को टैग कर सुझाव दिया कि शायद मुख्यमंत्री नए शब्द के चयन के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। उनका यह बयान तब आया है जब केंद्र की मोदी सरकार राज्य का नाम आधिकारिक रूप से 'केरलम' करने सहमति जता चुकी है।

महाराष्ट्र से एनसीपी पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतारेगी, बीजेपी के अंदर नामों को लेकर मंथन

–शिवसेना शिंदे गुट के लिए एक सीट सुरक्षित

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत में हलचल तेज हो गई है। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस लेकर अपने उम्मीदवार पर बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, सोमवार की रात प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की हुई बैठक में पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उतरने पर सहमति बनी है। बैठक में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। 26 फरवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग सकती है, जहां सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पार्टी इस बार राज्यसभा की चार सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसमें रामदास अठावले का नाम करीब तय है, जबकि विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर

अंतिम निर्णय होना बाकी है।

बात दें कि महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा की 7 सीटें खाली हैं और 286 विधायकों के आधार पर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के अनुसार, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। सिर्फ बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर कुल (131+1) यानी 132 विधायकों का समर्थन है, इस संख्याबल के दम पर 3 से 4 सांसद आसानी से भेज सकती है। वहीं शिवसेना (शिंदे गुट) अपने 58 विधायकों के साथ एक सीट सुरक्षित कर सकती है, जबकि एनसीपी (अजित पवार गुट) भी एक सीट जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अजित पवार की मौत के बाद उसके पास 40 विधायक हैं।

इसके मुकाबले महाविकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (ठाकरे गुट) शामिल हैं, के पास कुल मिलाकर करीब 49 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर एमवीए केवल एक सीट ही सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महायुति गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को सीमित सफलता मिलने की संभावना है।

उड़ान भरते ही विमान इंजन हुआ फेल, दिल्ली एसरपोर्ट पर कराई आपात लैंडिंग

–कॉकपिट में नहीं मिला फायर वार्निंग संकेत, विमान में सवार थे 150 यात्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइस जेट विमान की मंगलवार उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण लेह जाने के बजाय दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इंजन नंबर-2 फेल होने से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के बाद यात्रियों के लिए यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली से लेह जा रहे विमान को वापस बुलाना पड़ा। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कॉकपिट में फायर वार्निंग का कोई संकेत नहीं मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्लाइट एसजी121 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से

निकली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रू मेंबर्स को तकनीकी खराबी का पता चला। सावधानी बरतते हुए पायलटों ने विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया। विमान की पूरे प्रोटोकॉल के साथ लैंडिंग करवाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ मेडिकल टीम और फायर सर्विस भी वहां मौजूद थी।

बता दें इससे पहले असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन के एक विमान में 14 फरवरी को बम होने की धमकी मिली थी जिसके बाद विमान की तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। वहीं बीते साल 2 दिसंबर को कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो के एक विमान में बम की धमकी के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। विमान में बम की चेतावनी की धमकी ई-मेल से मिली थी जो कि बाद में फर्जी निकली। वहीं बीते साल ही 12 नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुंबई से वाराणसी जा रहे विमान के टॉयलेट में कागज पर बम लिखा मिलने के बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

कांग्रेस गुटबाजी, अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी से हाशिये पर!

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की लगातार गिरती राजनीतिक स्थिति और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बोरा ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई राज्यों में कांग्रेस की इकाइयां अंदरूनी गुटबाजी, आपसी अविश्वास और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की कमी के कारण हाशिये पर आ रही है। आलोचकों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया में कथित 'सुस्ती' और समय पर हस्तक्षेप न कर पाने की प्रवृत्ति पार्टी के लगातार क्षरण का कारण बन रही है।

कर्नाटक में सीएम सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। बताया जाता है कि राहुल गांधी की मुलाकातों के बावजूद मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुटों के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर संघर्ष जारी है। पार्टी ने राज्य इकाई भंग कर संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन असंतोष बना रहा। दिल्ली में जहां कभी शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पार्टी आज एकजुट चेहरा पेश करने में नाकाम है।

वहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेदों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन तब तक काफी क्षति हो चुकी थी। यूपी में संगठन भंग करने के बावजूद कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाई। पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में भी पार्टी अव्यवस्था का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ गठबंधन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका।

बिहार में राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को 'बोझ' के रूप में देखा गया। ओडिशा में संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को 2023 में सत्ता गंवाने की बड़ी वजह माना गया। गुजरात और महाराष्ट्र में भी पार्टी दो दशक से ज्यादा समय से बीजेपी को चुनौती देने में विफल रही है। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठबंधन के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभरे हैं, जिससे आगामी चुनावों से पहले असहज स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर कई राज्यों में लगातार गुटबाजी, नेतृत्व संकट और सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनौतियों के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है।

चोरी की 23 बाइक के साथ संगठित गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : जिले में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग पुलिस ने एक संगठित बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के उद्भेदन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच दल (रक्ळ) का गठन किया गया था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोकला गांव में चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद-बिक्री की जा रही है।सूचना के सत्यापन के बाद गठित टीम ने नापोकला एवं

आसपास के क्षेत्रों में सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सतीश प्रजापति (30 वर्ष), पिता बुधन प्रजापति, ग्राम-नापोकला, थाना बड़कागांव बताया।

मास्टर चाबी से करता था चोरी

कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से मास्टर चाबी के माध्यम से मोटरसाइकिल चोरी करता था। उसकी निशानदेही पर उसके घर एवं घर के पीछे छिपाकर रखी गई कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

ये सामान हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से 14 स्प्लेंडर, 3 पैशन प्रो, 2 अपाची, 2 पल्सर एवं 2 ग्लैमर मोटरसाइकिल के अलावा एक इंफिनिक्स मोबाइल जब्त किया है। सभी वाहनों के कागजात की जांच की जा रही है।

मामला दर्ज, सहयोगियों की तलाश

गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध बड़कागांव थाना कांड संख्या 27/26, दिनांक 24 फरवरी 2026 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।छापेमारी दल में अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता, डाडी कला ओपी प्रभारी सागेन मुर्मू, सअनि बसंत भगत सहित बड़कागांव थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।

पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना को दें, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

संक्षिप्त खबरें

खाटू श्याम भक्ति में रंगीं महिलाएं, फाल्गुन निशान यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

हजारीबाग(बिभा): फाल्गुन मास के पावन अवसर पर श्याम भक्त परिवार द्वारा आयोजित श्री श्याम रंगीलो निशान यात्रा में इस बार महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में निशान (ध्वज)लिए महिलाएं पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शोभायात्रा में शामिल हुईं। ढोल-नगाड़ों के बीच जब बाबा श्याम के भजन गूंजे तो श्रद्धालु खुद को झूमने से रोक नहीं पाए।यात्रा के दौरान महिलाओं ने हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा जैसे जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर निशान यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। आयोजकों के अनुसार फाल्गुन मास में निकलने वाली इस निशान यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया।

रंग रंगीला फाल्गुन: 27 फरवरी को गूंजेगा एकादशी कीर्तन

हजारीबाग(बिभा) : फाल्गुन मास के पावन अवसर पर शहर में भक्ति, संगीत और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को शाम 6 बजे से रंग रंगीला फाल्गुन कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य एकादशी कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर श्रद्धालु भक्त भजन-कीर्तन, संकीर्तन एवं प्रभु नाम स्मरण के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करेंगे।आयोजकों के अनुसार फाल्गुन का महीना स्वयं में आनंद, उत्साह और भक्ति का प्रतीक है। ऐसे में संगीतमय कीर्तन के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाने की तैयारी की गई है। मधुर भजनों और प्रभु नाम के संकीर्तन से उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय भजन मंडलियों द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ भी दी जाएंगी। यह भव्य आयोजन अग्रसेन भवन, मालवीय मार्ग में आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम के निवेदक श्री श्याम टाबरिया ने शहरवासियों से सपरिवार उपस्थित होकर कीर्तन का लाभ लेने एवं आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फाल्गुन के रंग और भक्ति की तरंग के साथ यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। फाल्गुन की मस्ती और भक्ति की शक्ति से सराबोर यह एकादशी कीर्तन न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी सुदृढ़ करेगा।

बसंत व होली स्वागत संग काव्य की सुरमयी संध्या: महिला काव्य मंच हजारीबाग इकाई की मासिक गोष्ठी संपन्न

हजारीबाग(बिभा) : महिला काव्य मंच की हजारीबाग इकाई द्वारा मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। बसंत ऋतु के आगमन एवं रंगों के पावन पर्व होली के स्वागत के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, स्नेह और संस्कारों की सुंदर छटा देखने को मिली।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में रागिनी दांगी उपस्थित रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच की अध्यक्षा पूनम तिवारी जी ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की। प्रदेश अध्यक्ष मोना बग्गा के सान्निध्य में हजारीबाग इकाई की मातृ-शक्तियाँ—पूजा परिणिती, जागृति शर्मा, तिशु सिंह ह्यतृष्णाह्ल, स्वाति, मिलन माला भगत, शिखा जैन एवं खुशबू कुमारी—ने सहभागिता निभाई। गोष्ठी में सभी कवयित्रियों ने बसंत, प्रेम, प्रकृति और होली के उल्लास पर आधारित भावपूर्ण कविताओं का पाठ किया। अबीर-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को होली की अग्रिम शुभकामनाएँ दी गईं, जिससे वातावरण रंगमय और आनंदित हो उठा।यह आयोजन जागृति शर्मा के निवास पर सम्पन्न हुआ, जहाँ आत्मीयता और साहित्यिक सौहार्द का सुंदर संगम देखने को मिला।अंत में प्रदेश अध्यक्ष मोना बग्गा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं रंगों की बहार बनी रहे, ऐसी मंगलकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह गोष्ठी न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का मंच बनी, बल्कि आपसी स्नेह, संस्कृति और परंपरा के उत्सव का भी प्रतीक सिद्ध हुई।

अबुआ दिशोम बजट नहीं, यह झारखंड का बबुआ बजट है: रंजन चौधरी

हजारीबाग(बिभा): झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए अबुआ दिशोम बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के लोकसभा क्षेत्र के सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने इसे दिशाहीन, आधारहीन और महज जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रजत जयंती वर्ष के नाम पर परोसा गया यह बजट असल में बबुआ बजट है, जिसके माध्यम से गठबंधन सरकार ने एक बार फिर झारखंडियों को ठगने का काम किया है। 10% बजट वृद्धि और मध्यम परियोजनाओं का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन वर्तमान बदहाल व्यवस्थाओं को देखते हुए इसके क्रियान्वयन पर गहरा संदेह है।

श्री श्याम फाल्गुन निशान ध्वज यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : श्याम भक्त परिवार हजारीबाग के द्वारा मंगलवार को श्री श्याम फाल्गुन निशान ध्वज यात्रा का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ मालवीय मार्ग स्थित नवनिर्मित श्याम मंदिर परिसर से आरंभ हुई यह दिव्य शोभायात्रा पूरे शहर में भक्ति की अलख जगाती हुई विभिन्न प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों से होकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से संपन्न पूजा-अर्चना के साथ हुआ। यजमान के रूप में बजरंग खेतान एवं उनकी धर्मपत्नी तथा नरेश वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी ने बाबा श्याम की पूजा-अर्चना कर शहरवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। पूजा के उपरांत जैसे ही निशान ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई, पूरा वातावरण हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा और जय श्री श्याम के गगनभेदी नारों से गुंजायमान हो उठा। शोभायात्रा का मुख्य

आकर्षण सुसज्जित भव्य रथ रहा, जिस पर प्रभु श्री श्याम की मनोहारी झांकी विराजमान थी। रथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रथ के पीछे राधा रानी की आकर्षक प्रस्तुति ने भक्तों को भावविभोर कर दिया। धार्मिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। इस भव्य आयोजन में लगभग 500 से अधिक महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं लाल और पीली साड़ियों में सुसज्जित होकर निशान ध्वज लिए भक्ति-भाव से चल रही थीं, जबकि पुरुष पारंपरिक कुर्ता-पायजामा में अनुशासित पंक्तियों में आगे बढ़ रहे थे। सभी श्रद्धालु एक स्वर में भजन-कीर्तन करते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिससे पूरा शहर श्याम मय हो गया।यात्रा के दौरान धार्मिक झांकियों ने विशेष आकर्षण बटोरा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एक सज्जन के द्वारा लंगूर के स्वरूप में बच्चों और बड़ों का मनोरंजन करते दिखाई दिए, वहीं अग्रिम पंक्ति में हनुमान स्वरूप धारण किए एक भक्त पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते नजर आए ढोल-नगाड़ों और भजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई स्थानों पर कई समाज एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया तथा श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। समाजसेवी मुन्ना सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और आयोजन की सराहना की। मंदिर परिसर पहुंचने के उपरांत बाबा श्याम की सामूहिक आरती की गई। आरती के समय उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक स्वर में जयकारे लगाए, जिससे वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो उठा। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। आयोजक मंडली ने बताया कि बाबा श्याम की असीम कृपा और आशीर्वाद से यह आयोजन लगातार 13 वें वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों, स्वागतकताओं तथा पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्था संभालने वाले कार्यकताओं के साथ महिला सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इसी भव्यता के साथ आयोजन जारी रखने का संकल्प दोहराया।

उप विकास आयुक्त ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की

बिभा संवाददाता

हजारीबागः उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निदेर्शानुसार उपविकास आयुक्त रिया सिंह ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में एसएमएस रिपोर्टिंग, छात्र-शिक्षक उपस्थिति, आईएफए (क्रऋअ) दवा वितरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण सहित विभिन्न बिंदुओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपविकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिदिन एसएमएस रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी योजनाओं से संबंधित अद्यतन डेटा ससमय उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को कहा गया।

बैठक के दौरान उपविकास आयुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं जैसे पेयजल सुविधा, नए भवनों का निर्माण, चहारदीवारी, किचेन शेड, बेंच-डेस्क आदि से संबंधित आवश्यकताओं की चेकलिस्ट उपलब्ध कराई। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार चेकलिस्ट भरवाकर निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जाए। पीएम श्री विद्यालयों से प्राप्त चेकलिस्ट की भी बैठक में समीक्षा की गई।

बैठक में उपविकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह के अलावा जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एमडीएम ऑपरेटर सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा में पेश हुए बजट को बताया निराधार

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : सदर विधानसभा के विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट को पूरी तरह निराधार, दिशाहीन और जनविरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की महिलाओं, युवाओं, किसानों एवं आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असफल रहा है।विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार ने कुल ?1,58,560 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है किंतु इस भारी-भरकम आंकड़े के बावजूद जमीनी विकास की स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आती। राजस्व आय को ?1,36,210.04 करोड़ तथा राजस्व व्यय को ?1,20,851.90 करोड़ दशार्या गया है परंतु इन आंकड़ों में आम जनता के जीवन स्तर में ठोस सुधार का कोई रोडमैप नहीं दिखता।उन्होंने विशेष रूप से कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर केवल योजनागत प्रावधान दिखाए गए हैं, लेकिन रोजगार, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए ठोस एवं नवीन पहल का अभाव

श्री प्रदीप प्रसाद, मा० सदस्य, हजारीबाग, 2

है।युवाओं के लिए कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन की दिशा में कोई स्पष्ट नीति या बड़े निवेश की घोषणा नहीं की गई है। किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए बजट में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के मद में आवंटन तो दशार्या गया है, परंतु पिछली योजनाओं के परिणामों की समीक्षा और जवाबदेही का अभाव है।विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल है, जिसमें पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जनता को छलावा परोसा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आधारभूत संरचना की चुनौतियों पर गंभीरता नहीं दिखाई।

झारखंड का अबुआ दिशोम बजट सिर्फ आंकड़ों की है बाजीगरी और जन-आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात: मनीष जायसवाल

बिभा संवाददाता

हजारीबागः झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकास का रोडमैप नहीं, बल्कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन की विफलता का एक निराशाजनक दस्तावेज है। रजत जयंती वर्ष के नाम पर परोसा गया यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन और आधारहीन है, जिसमें विजन का नितांत अभाव झलकता है। सरकार न तो राजस्व सृजन की कोई स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत कर पाई है और न ही विकास की कोई ठोस और दीर्घकालिक दिशा दिखा सकी है। यह बजट केवल आंकड़ों का एक ऐसा मायाजाल बनकर रह गया है, जिसका जमीनी हकीकत और झारखंड की आम जनता की जरूरतों से कोई सीधा सरोकार नजर नहीं आता। उक्त बातें झारखंड सरकार द्वारा मंगलवार

को पेश किए गए अबुआ दिशोम बजट पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने मनीष जायसवाल ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य का युवा वर्ग आज खुद को सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इस बजट में न तो रोजगार के लिए कोई ठोस पहल है और न ही छात्रवृत्ति या अवसरों के विस्तार की कोई स्पष्ट योजना। 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार ने अनुबंधकर्मियों के भविष्य और युवाओं के सशक्तिकरण पर पूर्ण चुप्पी साध रखी है। इसी तरह अन्नदाता किसानों के लिए कोई सार्थक राहत नहीं दी गई है और न ही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु कोई मजबूत कदम उठाया गया है। वृद्ध और दिव्यांगजनों की पेंशन में भी कोई सम्मानजनक वृद्धि न करना सरकार के संवेदनहीन दृष्टिकोण को उजागर करता है ।

सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी और पेट स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाओं की घोषणा केवल ₹मुंगेरीलाल के हसीन सपने₹ दिखाने जैसा है, क्योंकि वर्तमान में संचालित बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। झारखंड को आज खोखले दावों और कागजी घोषणाओं की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। यह बजट जन अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह विफल साबित हुआ है और राज्य की जागरूक जनता इस भेदभावपूर्ण और निराशाजनक बजट को कभी स्वीकार नहीं करेगी। संवेदनहीनता और जुमलेबाजी का यह दौर अब झारखंड की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है ।

अबुआ दिशोम बजट पर पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा

जन आकांक्षाओं को साकार करने वाला यह बजट है

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए अबुआ दिशोम बजट को लेकर पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने सरकार की सराहना करते हुए इसे राज्य की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का दस्तावेज बताया है। मुन्ना सिंह ने कहा कि यह बजट वास्तव में अबुआ यानी हमारे लोगों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर जो प्रावधान किए हैं, वे झारखंड के समग्र विकास की स्पष्ट रूपरेखा पेश करते हैं। उनके अनुसार, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को मजबूत करने की

ठोस कार्ययोजना है। उन्होंने विशेष रूप से कृषि, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की सराहना की। उनका कहना था कि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं को नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मुन्ना सिंह जी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना करते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों की अनदेखी की गई है, वहीं राज्य सरकार ने स्थानीय जरूरतों और जनता की राय को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यह बजट जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बजट सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु बनेगा तथा राज्य के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगा।

झारखंड के समग्र विकास और जनकल्याण को समर्पित दूरदर्शी बजट: विकास राणा

बिभा संवाददाता

हजारीबागः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय समिति सदस्य विकास राणा ने कहा कि झारखण्ड सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट समाज के सभी वर्ग के अंतिम व्यक्ति को लाभ लाभ पहुँचाने वाला बजट है ! झारखण्ड के विकास को अग्रसर करने वाला बजट है ! महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ सभी बातो को ध्यान में रखते हुए जनता के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालते हुए एक विकासोन्मुखी बजट पेश किया गया है जो काफी

सराहनीय है ! राज्य के हेमन्त सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार दूरदर्शिता की सोच वाली गम्भीर और जवाबदेही के साथ राज्य को इस बजट के माध्यम से विकसित करने की ओर अग्रसर है !

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: ओ/एसी/टी/147-149/25-26 (खुली), दिनांक 20.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएँ (खुली) आमंत्रित की जाती हैं: **क्रम संख्या: 1, केस संख्या** : ओ-एसी-टी-147-25-26, **कार्य का नाम:** वरिष्ठ डीईएन/1/आसनसोल के तहत एईएन/मुख्यालय/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में मंडल रेलवे अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 1,53,74,929.02, **बयाना राशि :** रु. 2,26,900/- **क्रम सं. 2, केस संख्या:** ओ-एसी-टी-148-25-26, **कार्य का नाम:** ट्रैक मानकीकरण के लिए दुमका स्टेशन यार्ड के सुधार के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 78,50,916.50, **बयाना राशि :** रु. 1,57,000/-, **क्रम सं. 3, केस सं.** : ओ-एसी-टी-149-25-26, **कार्य का नाम:** एसटीएन-जेएजे मेन लाइन एमडीपी-जीआरडी और जेएसएमई-बीडीएमई ब्रांच लाइन में लेवल क्रॉसिंग रोड सरफेस में सुधार के साथ-साथ पुराने, जीर्ण-शीर्ण गेट लॉज को बदलने सहित एसओडी उल्लंघन से बचने के लिए नए गेट लॉज के निर्माण द्वारा गेट लॉज को स्थानांतरित करने के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य :** रु. 1,01,94,897.33, **बयाना राशि :** रु. 2,01,000/- **कार्य की समापन अवधि:** क्रम सं. 1 हेतु 09 माह, क्रम सं. 2 हेतु 06 माह और क्रम सं. 3 हेतु 12 माह। **बंद होने की तिथि और समय:** 18.03.2026 को 12.00 बजे प्रत्येक हेतु। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** में देखा जा सकता है।

ASN-364/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

टी20 विश्व कप के सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगी श्रीलंका

कोलंबो (एजेंसी)। मेजबान श्रीलंकाई टीम बुधवार को अपने दूसरे सुपर-8 मैच में बुधवार को न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। श्रीलंकाई टीम को अपने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब अगर वह न्यूजीलैंड से हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मेजबान श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज अपने पहले मैच में असफल रहे थे, ऐसे में उसे अगर कीवी टीम से जीतना है तो स्पिनरों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंकाई 147 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाए थे। श्रीलंका की पिचें बल्लेबाजी के लिए कठिन मानी जाती हैं। इसके अलावा इन मैदानों पर बड़े शॉट खेलना भी कठिन होता है।

सुपर आठ के पहले मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाते दिखे थे और उसकी टीम को अपनी इन गलतियों से सबक लेना होगा। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने टीम के खराब प्रदर्शन पर कहा, 'यह एक टी20 मैच है, इसलिए जाहिर है कि आप अधिक से अधिक रन बनाने की कोशिश करते हैं पर जब गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही होती है, तो कहना आसान है पर रन बनान कठिन है।'

पथुम निसांका ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है जबकि बाएं हाथ के स्पिनर दुनिथ वेलालेज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश से नहीं हो पाया था। जिससे दोनो को ही एक-एक अंक मिला है। कीवी टीम के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनर सहित अच्छे स्पिनर हैं जो श्रीलंका के बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे।

दोनों टीम सुपर आठ में पहली जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और टिम सीफर्ट की जोड़ी ने लीग चरण के दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी की है। इसके अलावा रचिन रविंद्र भी कनाडा के खिलाफ अर्धशतक लगाकर फॉर्म में आ गये हैं। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए कीवी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना आसान नहीं रहेगा।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा।

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी, कोल मैककॉन्ची।

अभिषेक, तिलक और रिंकू पर लटक रही तलवार

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच टेन डोइशे और सितांशु का कहना है सुपर-8 के अगले मैचों के लिए टीम की फिर से समीक्षा करते हुए बदलाव किये जायंगे। ऐसे में तय है कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की जगह खतरे में हैं। इन तीनो में से किसी एक का बाहर जाना तय है। ये तीनो ही अब तक इस टूर्नामेंट में असफल रहे हैं। इसके अलावा टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उतारे जाने की रणनीति पर भी फिर विचार करेगा। दक्षिण अफ्रीका से पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद से ही उसके लिए अब बचे हुए दोनो मैच बड़े अंतर से जीतना जरुरी है। इसलिए फार्म से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को बनाये रखने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। अभिषेक अब तक चार मैचों में 15 रन जबकि तिलक वर्मा पांच मैचों में 107 रन ही बना पाये हैं। इसके अलावा रिंकू भी फिनिशर की भूमिका में विफल रहे हैं। वह 29 गेंदों में 82.75 की स्ट्राइक रेट से केवल 24 रन ही बना पाये हैं।

कोटक ने कहा, अगर मुख्य कोच और टीम प्रबंधन को लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने हैं तो हम करेंगे। अब इस पर विचार हो रहा है कि अगर हमें बदलाव करना है तो वह क्या होगा और कैसे होगा। अब हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं कि हमें कुछ भी बादलाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं डोइशे ने माना है कि टीम में बैकअप में विशेषज्ञ बल्लेबाजों की की है। उन्होंने कहा, या तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं जो आपको लगता है कि पिछले डेढ साल में अच्छा खेल रहे हैं, भले ही अभी रन नहीं बना पा रहे हैं। या फिर बदलाव करके संजू सैमसन को लाते हैं जो शानदार खिलाड़ी है और उनके आने से शीर्षक्रम में दायें और बाएं का संयोजन लाभकारी रहेगा। उन्होंने कहा, अगले दो अहम मैचों से पहले सैमसन को शामिल करने के बारे में विचार होगा। साथ ही कहा कि अभिषेक और तिलक का फॉर्म चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ये दोनो ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाये हैं। वहीं अभिषेक को सलाह दिये जाने को लेकर कोटक ने कहा, बल्लेबाजी कोच होने के कारण मेरा मानना है कि उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देने की जरुरत नहीं है। उसके दिमाग को ठीक से काम करने दें। लगातार सलाह से मानसिक दबाव पड़ता है जिससे बल्लेबाज का मनोबल गिरता है। उसे अपने अनुसार खेलने देना ही बेहतर रहेगा

तिलक अंतिम ग्यारह में शामिल करने के लायक नहीं : श्रीकांत

–सैमसन को मिले अवसर

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कहा है कि तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। इसलिए अंतिम ग्यारह में उनकी जगह नहीं बनती है। श्रीकांत के अनुसार अभी के समय में तिलक को टीम में रखना फायदेमंद नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी वह केवल एक रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। इससे अन्य बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था। उन्हें ऐसे समय पर अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिये थी। , क्योंकि ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

अब तक विश्वकप के पांच मैचों में तिलक 118.88 के स्ट्राइक रेट से 107 रन बना पाये हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक के आउट होने के तरीके से श्रीकांत नाराज हैं। उनका कहना है कि अब सुपर-8 के बचे हुए मैचों में संजू सैमसन को उनकी जगह शामिली किया जाना चाहिये। श्रीकांत ने कहा, ÷अगर सैमसन को 11 में आना है, तो तिलक के लिए कोई जगह नहीं है। कई अनय लोग भी तिलक के बल्लेबाजी के तरीके से हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शॉट खेला, उसके लिए उन्हें 11 से बाहर किए जाने की पूरी संभावना है। यह काफी खराब शॉट था और ऐसा शॉट खेलने के बाद वह क्रीज पर टिके रहने के लायक नहीं थे।÷

श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली के संन्यास के बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम मुश्किल में आ जाती है।

ब्रिस्बेन वनडे में टीम इंडिया की करारी हार, स्मृति मंधाना का अर्धशतक गया बेकार

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। मंगलवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए वनडे द्विपक्षीय श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को छह विकेट से हरा दिया। एलिसा हीली की अगुवाई वाली टीम ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में 1-2 से हार के बाद इस मैच में उतरी थी। उन्होंने मेहमान टीम को 214 रनों पर रोककर 215 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए, कप्तान हीली ने फोएबे लिचफील्ड (32 गेंदों में 32 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की। श्री चरानी ने 11वें ओवर में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने इसी ओवर में जॉर्जिया वोल को भी आउट किया। आउट होने वाली कप्तान हीली ने 70 गेंदों में 50 रन बनाए। उन्होंने बेथ मूनी (79 गेंदों में 76 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की। एनाबेल सदरलैंड (44 गेंदों पर 48 रन नाबाद) और गार्डनर (4 गेंदों पर 5 रन नाबाद) नाबाद रहीं और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल कर ली। मैच जिताने वाली इस शानदार पारी के लिए मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनते हुए, भारतीय महिला टीम ने पहले ही ओवर में अपना पहला विकेट खो दिया जब मेगन शट ने विकेट के सामने प्रतिका रावल को कैच दे दिया। शेफाली वर्मा एक रन पीछे बल्लेबाजी करने आईं और लय हासिल नहीं कर सकीं। उन्होंने 17 गेंदों में सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। डार्सी ब्राउन ने उन्हें आठवें ओवर में कैच आउट किया। जेमिमा रोड्रिग्स भी सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गईं। पावरप्ले खत्म होने के तुरंत बाद एशले गार्डनर ने उन्हें आउट कर दिया। बेथ मूनी ने विकेट के पीछे एक शानदार कैच पकड़ा।

स्मृति मंधाना ने 20वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। मैकग्राथ ने अपने अगले ओवर में मंधाना को 58 रन पर आउट कर दिया। उन्होंने अपनी प्रभावशाली पारी में सात चौके लगाए। दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और जल्द ही सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद ऋचा घोष कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ शामिल हुईं और दोनों ने छठे विकेट के लिए 37 रन जोड़े।

आईपीएल की तरह बदलाव वाली नीति विश्वकप में नहीं चलती : अश्विन

नई दिल्ली । भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने टीम प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाये हैं। अश्विन के अनुसार टी20 विश्वकप जीतने के लिए टीम प्रबंधन को आईपीएल वाली बदलाव की सोच से बाहर आना होगा। अश्विन ने कहा कि प्रबंधन ने जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर बिठाया वह समझ से परे हैं। साथ ही कहा कि ये सब आईपीएल में चलता पर विश्वकप में नहीं। अश्विन ने कहा कि इस प्रकार के बदलाव आईपीएल में इसलिए चलते हैं कयोंकि टीम को 14 गेम खेलने होते हैं पर आईसीसी टूर्नामेंट में बदलाव कम से कम होने चाहिये और जितना आज टीम को स्थर रखते हैं उतना ही लाभ होता है। अश्विन ने साथ ही कहा, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अक्षर ने पिछले विश्व कप में किस प्रकार का प्रदर्शन किय था।

धोनी ऐसी बाइक चलाते दिखे जो भारत में लांच ही नहीं हुई थी

रांची । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाइक ?स के काफी शौकीन हैं। रांची की सड़कों पर भी वह कई बार बाइक चलाते दिखते हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक बाइकें हैं। जिसमें डुकाटी, कावासाकी, हार्ले-डेविडसन, यामाहा के अलावा कई विंटेज और हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स भी हैं। वहीं अब धोनी एक वीडियो में ऐसी बाइक चलाते दिखें हैं जो भारत में कभी लांच ही नहीं हुई थी। ये यामहा की एसआर400 है। यह पुराने जमाने की ऐसी बाइक है जो भारत में कुछ ही लोगों के पास हैं। ये क्लासिक रेट्रो-स्टाइल मोटरसाइकिल साल 1970 की यूनिवर्सल जापानी मोटरसाइकिल्स से प्रेरित होकर 1978 में बनायी गयी थी पर 2021 में इसे बनाना बंद कर दिया गया। इसका कारण है कि यह पुरानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक थी और प्रदूषण के नये मानकों पर खरी नहीं उतरी। यह बाइक कस्टमाइज़ेशन के कारण काफी लोकप्रिय हुई है। इससे भारत में कभी भी आधिकारिक रुप से लांच नहीं किया गया केवल ये आयात की गयी है। ये एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि दोपहिया वाहनों की दुनिया में एक 'टाइम मशीन' की तरह है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 399सीसी का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन है। इस बाइक की ट्यूनिंग इस तरह की गई है कि यह कम रफ्तार पर भी काफी अच्छी चलती है। इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का विकल्प भी नहीं है और किक से स्?टार्ट होती है। ये ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी काफी अच्छे से चलती है। इसमें सिग्नेचर टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट और चमकता हुआ क्रोम एग्जॉस्ट दिया गया है। ये बाइक 130-140 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है।

गंभीर की पॉलिटिक्स ने टीम इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंचाया, पूर्व पाक बल्लेबाज का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर तीखी टिप्पणी की है। शहजाद का दावा है कि गंभीर की राजनीतिक पृष्ठभूमि का असर टीम के माहौल पर पड़ा है। साथ ही उन्होंने चयन फैसलों और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

सुपर 8 हार के बाद बढ़ा दबाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली बड़ी हार ने भारतीय खेमे में चिंता बढ़ा दी है। इस हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है, जिससे कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट पर दबाव साफ दिख रहा है। कुछ चयन फैसलों ने भी बहस को जन्म दिया। अहम मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका देने पर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों ने सवाल उठाए।

पॉलिटिक्स टीम में भी आ गई : शहजाद

अहमद शहजाद ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान गंभीर का दृष्टिकोण बदल गया। उनका इशारा उस समय की ओर था जब गंभीर सांसद रहे। शहजाद का मानना है कि राजनीति का असर अब टीम प्रबंधन में भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, किसी भी खेल में सफलता के लिए पूर्ण फोकस जरूरी होता है, और अगर ध्यान बंटे तो उसका असर टीम के माहौल पर पड़ सकता है।

कुलदीप यादव को लेकर उठे सवाल

शहजाद ने यह भी कहा कि टीम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कुलदीप यादव का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सीमित मौके मिले हैं। उनका कहना था कि कुलदीप जैसे मैच-विनर स्पिनर को लगातार बाहर रखना समझ से परे है। टी20 फॉर्मेट में विविधता और विकेट लेने की क्षमता बेहद अहम होती है, और कुलदीप उस भूमिका को निभा सकते हैं।

कप्तान के साथ विवाद की चर्चा

शहजाद ने एक कथित घटना का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कुलदीप के बीच कहासुनी की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी अनबन से इनकार किया। फिर भी शहजाद का मानना है कि कुलदीप को बाहर रखने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

चयन और रणनीति पर बहस

टीम इंडिया के चयन और रणनीति को लेकर चर्चा तेज है। आलोचकों का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट में टीम कॉम्बिनेशन का संतुलन बेहद अहम होता है। स्पिन विकल्पों और ऑलराउंडर्स के बीच सही तालमेल बनाना जीत की कुंजी साबित हो सकता है। इसके बावजूद यह भी तथ्य है कि गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत ने हालिया बाइलेटरल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है।

एफआई प्रो लीग में स्पेन ने भारतीय हॉकी टीम को हराया

होबार्ट । स्पेन ने एफआई एच प्रो लीग के ऑस्ट्रेलियाई चरण में भारतीय हॉकी टीम को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। दोनो टीमों के बीच तय समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा पर इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपना पर गोल नहीं कर पायीं। 19वें मिनट में कप्तान हार्दिक सिंह के एक पास पर मनिंदर सिंह ने गोल दागकर भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने जबरदस्त प्रहार किये पर भारतीय रक्षा पंक्ति और गोलकीपर ने बचाव कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले किये। स्पेन के ब्रूनो फॉन्ट ने अंतिम क्षणों में शानदार गोल दागकर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वहीं इसके बाद हुए शूटआउट में भारत के अभिषेक और हार्दिक सिंह गोल नहीं कर पाये जिससे स्पेन ने 4-3 से मुकाबला जीत लिया।

बीसीएल में खेलते नजर आयेंगे धवन

मुम्बई। हाल में आयरलैंड की सोफी शाइन से दूसरी शादी करने वाले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन अब बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) के दूसरे सत्र में खेलते नजर आएंगे। धवन बीसएल के दूसरे सत्र में 'यूपी ब्रिज स्टार्स' की ओर से खेलेंगे। धवन जैसे अनुभवी क्रिकेटर का लाभ टीम के युवाओं को मिलेगा। इससे पहले इसे लीग के पहले सत्र में भी धवन ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। बिग क्रिकेट लीग का आयोजन ग्रेटर नोएडा के खेल परिसर में होगा। ये टूर्नामेंट 11 मार्च से शुरु होगा और इसका खिताबी मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा। यूपी ब्रिज स्टार्स प्रबंधन को उम्मीद है कि धवन की कप्तानी में टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगी। उनके रहने से से युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का काफी अवसर मिलेगा। बीसएल एक ऐसा टूर्नामेंट हैं जिसमें गली-मोहल्लों में खेलने वाले प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का अवसर मिलता है। इस लीग में डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, वकील, किसान या किसी भी अन्य पेशे से जुड़ा व्यक्ति खेल सकता है। खास बात ये है कि आम खिलाड़ियों को भी अंतररष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है।

जब हम वेस्टइंडीज से खेलेंगे तो नेट रन-रेट जरूर मायने रखेगा : पार्थिव पटेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच में अहमदाबाद में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा। जियोस्टार के'फॉलो द ब्लूज' पर बात करते हुए, जियोस्टार एक्सपट 'पार्थिव पटेल ने भारत की हार, पावरप्ले में उनकी बैटिंग को लेकर चिंताओं और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच के लिए प्लेइंग ढ्ढ में संभावित बदलावों का विश्लेषण किया।

पार्थिव पटेल ने भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जीत पर कहा, '12 मैचों की जीत का सिलसिला पक्का खत्म हो गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेला। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बनाया था और अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। हालांकि, हार का मार्जिन काफी है, और नेट रन-रेट निश्चित रूप से तब काम आएगा जब हम 1 मार्च को कोलकाता में वेस्ट इंडीज का सामना करने जाएंगे। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी जीत है, और यह सभी मुश्किलों के बावजूद मिली, यह देखते हुए कि इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही थी। आपको दक्षिण अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा। हां, उन्हें कुछ समय के लिए अहमदाबाद में खेलने का फायदा मिला, लेकिन यह हमारा घर है। जाहिर है, भारतीय टीम वापस जाकर यह देखना चाहेगी कि क्या उन्होंने चीजों को सिंपल रखने के बजाय उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था।'

पावरप्ले में भारत को जरूरी शुरुआत नहीं मिलने पर पार्थिव पटेल ने कहा, 'सिर्फ इस गेम में ही नहीं, बल्कि नामीबिया या अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भी, हालांकि वह बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट था, लेकिन जल्दी विकेट खोना भारत के लिए चिंता की बात रही है। जिस तरह से भारत ने पावरप्ले में विकेट खोए हैं, खासकर ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ, वह चिंता की बात है। इस बार यह मार्करम के लिए था। वे बहुत ज़्यादा शॉट खेल रहे हैं, एंगल के खिलाफ जा रहे हैं। शायद वे बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर टॉप पर तीन लेफ़्ट-हैंडर होने पर। वे सूर्यकुमार को नंबर तीन पर भेज सकते थे। मुझे लगा कि भारत इस गेम में ऐसा कर सकता था। जब आप हाई-रिस्क, हाई-रिवॉड 'वाला गेम खेलते हैं, तो ऐसे दिन आना तय है।'

पटेल ने संजू सैमसन की प्लेइंग ढ्ढ में वापसी पर कहा, 'मैं अक्षर पटेल को टीम में वापस आते देखना चाहूंगा। उन्होंने पहले भी अहम पारियां खेली हैं। हां, मैच-अप की भी अहमियत है, लेकिन मैं अक्षर पटेल को जरूर लाऊंगा। संजू सैमसन का भी सवाल है। चेन्नई में अब उनकी घर वापसी भी हो सकती है। यह कुछ ऐसा है जिस पर भारत जरूर विचार करेगा, खासकर यह देखते हुए कि भारतीय लेफ्ट-हैंडर ऑफ-स्पिनर के खिलाफ बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, तो सिकंदर रजा भी पावरप्ले में काम आ सकते हैं। मैं तिलक की जगह संजू सैमसन को नहीं उतारूंगा। हां, संजू सैमसन भी अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। या शायद, भारत बैटिंग ऑर्डर बदलने की कोशिश कर सकता है, फिर सूर्या को नंबर तीन पर बैटिंग करनी होगी।'

एआई के दौर में भारत की युवा शक्ति भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा-सम्पन्न इकोसिस्टम बनाना

बिहान भारत

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026, का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को एक मजबूत विजन के साथ हुआ, जिसमें भारत के युवाओं को देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यात्रा के केंद्र में रखा गया है। भविष्य के स्वप्न से कहीं ज्यादा, यह सम्मेलन एआई को एक बदलाव लाने वाली क्षमता के रूप में प्रस्तुत करता है जो पहले से ही रोजगारों और आजीविका को बदल रही है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो इस जनसांख्यिकीय पॉवरहाउस को आर्थिक रफ़्तार के इंजन के तौर पर पेश करता है।

यह सम्मेलन निष्क्रिय शिक्षण से सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव, अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार को फिर से परिभाषित करना, कौशल पर ध्यान देना और उद्योग जगत की आवश्यकताओं के साथ शिक्षा को समकालीन बनाने की शीघ्र जरूरत को दिखाता है। इसका मुख्य ध्यान रोजगार, उत्पादन बढ़ाने और कक्षा से एआई-जनित करियर तक आसान मार्ग प्रशस्त करने पर है।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, युवा नवोन्मेषक अभिनव चुनौती, स्टार्टअप गतिविधियों और प्रत्यक्ष समाधान प्रदर्शन जैसे प्रायोगिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संरचित जुड़ाव कौशल को बाजार की जरूरतों से जोड़ते हैं और भारत के युवाओं की क्षमता को उत्पादक क्षमता में बदलते हैं। यह सम्मेलन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे उभरते क्षेत्र में रोजगार सृजन को तेज करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिनसे वर्ष 2030 तक लगभग 2 मिलियन रोजगार सृजन होने का अनुमान है। युवाओं के कौशल और रोजगार सृजन के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को साझा करते हुए, भारत अपनी एआई रणनीति और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के आधार के रूप में जनसांख्यिकीय लाभ को मजबूत कर रहा है।

भारत के प्रतिभा-सम्पन्न समूह के लिए एक अवसर के रूप में एआई

एआई तेजी से भारत के बड़े प्रतिभा सम्पन्न समूह के लिए एक बदलाव लाने वाले अवसर के तौर पर उभर रहा है। रोजगार के परिवेश को बदलकर, एआई नई भूमिकाओं का सृजन कर रहा है, उत्पादकता बढ़ा रहा है, और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के मार्ग में वृद्धि कर रहा है। भारत एआई को युवाओं रोजगार और कौशल को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक माध्यम मानता है, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी को सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और कौशल विकास के साथ जोड़ता है।

एआई कौशल की बढ़ती मांग

एआई कौशल और रोजगारों की बढ़ती मांग युवा भारतीयों के लिए अवसरों को बदल रही है। जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच, दक्षिण एशिया में एआई से जुड़ी रोजगार पोस्टिंग सभी पदों के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गईं, जिसमें एआई कौशल की मांग गैर-एआई भूमिकाओं के मुकाबले 75 प्रतिशत ज्यादा तेजी से बढ़ी। यह बदलाव भारत के श्रम बाजार में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है—एक ऐसा बदलाव जो डिजिटल रूप से सक्षम प्रवाह, अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता और बहुविषयक विशेषज्ञता को तेजी से सकारात्मक लाभ दे रहा है। भारत के युवाओं के लिए, एआई सिर्फ.एक तकनीकी दौर नहीं है, बल्कि प्रौदयौगिकी और आस-पास के क्षेत्रों में कौशल-प्रखर, भविष्य के लिए तैयार रोजगार की ओर एक सुस्पष्ट मार्ग है।

एआई-तैयार युवा कौशल के लिए नीतिगत समर्थन

एआई को एक रणनीतिक रोजगार संचालक के तौर पर पहचानते हुए, केन्द्रीय बजट 2026-27 ने एआई कौशल और योग्यता विकास पर सरकार के ध्यान को और मजबूत किया। बजट ने ऑरेंज इकोनॉमी को प्राथमिकात दी, जो एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट और इमर्सिव मीडिया जैसे एआई से जुड़े क्षेत्रों के साथ परस्पर संबंध रखती है। इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आईआईसीटी), मुंबई को 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एआई-से जुड़े विषय सृजन लैब्स बनाने के लिए समर्थन दिया, जिससे युवाओं के लिए भविष्य के तैयार कौशल हासिल करने और एआई-केन्द्रित रोजगार भूमिका में आने के मार्ग खुलेंगे। इस पहल से लगभग 20 लाख नए रोजगार सृजन होने का अनुमान है, जिससे पूरे भारत में छात्र, सृजनकर्ता और युवा पेशेवर के लिए रोजगार के अवसर सीधे तौर पर बढ़ेंगे।

बजट ने एआई और उभरती तकनीकों को सभी क्षेत्रों में रोजगार और कौशल को आकार देने का केन्द्र बिन्दु बताया। इसने एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव रखा ताकि यह पता लगाया जा सके कि एआई और उससे जुड़े टेक रोजगार और कौशल आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करती हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कार्य और उद्य मांग को दूर करना है।

एआई बुनियादी ढांचे तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण

भारत के कौशल समूह में अवसर बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सभी की बराबर पहुंच भी जरूरी है। इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत, सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने और वर्तमान 38,000 जीपीयू से आगे कंप्यूट क्षमता बढ़ाने के लिए 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं, साथ ही 20,000 और हाई-एंड जीपीयू जोड़े जाने हैं। 65 रूपए प्रति घंटे की सब्सिडी वाली दर पर मिलने वाला यह कंप्यूट एक्सेस स्टार्टअप्स, युवा इनोवेटर्स और सरकारी संस्थानों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है। कंप्यूट, डेटासेट और मॉडल इकोसिस्टम तक पहुंच को लोकतंत्रीकरण कर-के, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि एआई का अवसर सिर्फ.बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि देश भर के उभरते हुए प्रतिभाओं के लिए भी उपलब्ध हो। 58,000 से ज्यादा जीपीयू तक बढ़ाने की योजना एआई इकोनॉमी में सबको शामिल करने, ज़िम्मेदार इनोवेशन और व्यापक स्तर पर भागीदारी के लिए देश की वचनबद्धता को मजबूत करती है।

कौशल क्षमता, नवोन्मेष और पहुंच को एक साथ लाकर, एआई युवाओं द्वारा संचालित आर्थिक वद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन रहा है।

प्रतिभायुक्त एआई-तैयार कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास

भारत सरकार विद्यालयी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और पेशेवर कौशल उन्नयन में मिलकर काम करके एक बड़ी एआई प्रतिभा सम्पन्न श्रृंखला तैयार कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य युवाओं को उद्योग की मांग के हिसाब से बेसिक, इंटरमीडिएट और अत्याधुनिक एआई क्षमता प्रदान करना है।

विद्यालयों में बुनियादी एआई साक्षरता राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

एनईपी 2020 डिजिटल और एआई साक्षरता को आवश्यक योग्यता के तौर पर प्राथमिकता देता है, जिसमें अगली पीढ़ी को तेजी से प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव के लिए तैयार करने के लिए सभी शैक्षिक स्तर पर कम्प्यूटेशनल विचारधारा और एआई अवधारणा को शामिल किया गया है। यह समग्र पहुंच डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक एआई सिद्धांत के बारे में शीघ्र जानकारी सुनिश्चित करता है, प्राथमिक शिक्षण से ही नवोन्मेष की संस्कृति को बढ़ावा देता है और भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय एआई इकोसिस्टम में भविष्य के लिये तैयार योगदानकर्ता के तौर पर तैयार करता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (एआई एंड सीटी): एआई एंड सीटी पहल, ग्रेड 3 से शुरू होकर और धीरे-धीरे ₹एआई फॉर पब्लिक गुड₹ की ओर बढ़ते हुए, सीखने, सोचने और सिखाने के तरीकों को मजबूत करके शिक्षण तरीकों को फिर से परिभाषित करती है। यह बुनियादी पहल नैतिक एआई तरीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करती है, जिससे युवा सीखने वाले एल्गोरिदम, समस्या-समाधान और सामाजिक एप्लीकेशन को जल्दी समझ पाते हैं, जिससे एआई-प्रधान भविष्य के लिए संज्ञानात्मक रूप से अनुकूल बनता है।
- वाईयूवीएआई (एआई के साथ उन्नति के लिए युवा): नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के साथ शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वाईयूवीएआई, कक्षा 8-12 के छात्रों को आठ विषयपरक क्षेत्रों में व्यवहारिक एआई समाधान तैयार करने में सहायता करता है।
- सभी के लिए युवा एआई: सभी के लिए युवा एआई 11 भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु) में एक नि:शुल्क राष्ट्रीय एआई साक्षरता पाठ्यक्रम देता है। इसमें दीक्षा, आईगॉट कर्मयोगी और फ्यूचरस्किल्स प्राइम के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ नागरिकों को एआई की बेसिक जानकारी देना है। यह बड़े स्तर की ज्ञान पहल को सबके लिए उपलब्ध कराती है, शहर-गांव के बीच की दूरी को पाटती है, और एआई को एक जरूरी जीवन कौशल के तौर पर बढ़ावा देती है, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है और प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने की तैयारी होती है।

व्यावसायिक और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण

- कौशल भारत मिशन और एसओएआर पहल: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, एआई को पेशेवर प्रशिक्षण में समेकित करता है। एसओएआर (स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस) पहल के तहत दिसंबर 2025 तक माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एनएएसएसओएम के साथ साझेदारी के जरिए 1.34 लाख छात्रों और शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। प्रेसिडेंट के #स्किलदनेशन चुनौती के साथ, यह बेसिक और एप्लाइड एआई पाठ्यक्रम देता है, जिससे कार्यबल स्थानांतरण तेज होता है और उच्च-मांग वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ता है।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम पहल: यह पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेसकॉम के बीच एक सहयोग है, जो एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी नई प्रौद्योगिकी में पेशवरों के कौशल उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करती है। यह पहल नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स (एनओएस) और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनक्यूएफ) के समानुकूल है, जिससे सीखने वाले मांग के अनुरूप कौशल हासिल कर पाते हैं जिन्हें नियोक्ता भी बहुत महत्व देते हैं। 25.3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सीखने वाले और 3,000+ पाठ्यक्रम और मार्ग के साथ, यह प्लेटफॉर्म सीधे कार्यबल हस्तांतरण में योगदान देता है, जिससे सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है।

- स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध - एसआईडीएच): एमएसडीई का स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) कौशल विकास को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है, जो विभिन्न शिक्षार्थियों की दक्षताओं के अनुरूप प्रारंभिक से लेकर उन्नत स्तर तक के एआई और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक सुगम पहुंच प्रदान करके, यह आजीवन शिक्षण, क्षेत्रीय समावेशन और मापन योग्य कौशल उन्नयन का समर्थन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक इच्छुक पेशेवर अपनी पृष्ठभूमि या स्थान की परवाह किए बिना एआई-केंद्रित करियर की ओर अग्रसर हो सके।

उन्नत एआई प्रतिभा और अनुसंधान इको-सिस्टम

- इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स: इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों के लिए फैलोशिप और विशेष कौशल-संवर्धन पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक विशिष्ट एआई इको-सिस्टम का निर्माण करता है, जो दिसंबर 2025 तक 500 पीएचडी शोधार्थियों, 5,000 स्नातकोत्तर छात्रों और 8,000 स्नातक छात्रों को सहायता प्रदान करता है। यह लक्षित पहल शोध प्रतिभा को पोषित करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उन्नत एआई विशेषज्ञों की एक सतत आपूर्ति का निर्माण करती है।
- इंडियाएआई डेटा और एआई लैब्स: इंडियाएआई डेटा और एआई लैब्स, जिनकी स्थापना एनआईईएलआईटी के माध्यम से टियर-2/3 शहरों में 27 केंद्रों में की गई है और 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 174 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त हैं, एआई पाठ्यक्रम, डेटा क्यूरेशन, एनोटेशन, क्लीनिंग और एप्लाइड डेटा साइंस पर जोर देती हैं। ये केंद्र उच्च स्तरीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण करते हैं, जमीनी स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं और व्यावहारिक प्रशिक्षण को सक्षम बनाते हैं, जिससे महानगरों से परे एआई क्षमताओं का समान वितरण सुनिश्चित होता है।
- कक्षाओं से लेकर उन्नत प्रयोगशालाओं तक, यह बहुस्तरीय संरचना व्यापक पहुंच, क्षेत्रीय समानता और उद्योग संरेखण की गारंटी देती है, जिससे भारत के युवाओं को नैतिक एआई नवाचार और एआई-संचालित अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाया जा सके।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में युवाओं का सशक्तिकरण

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने भारत की एआई परिवर्तन यात्रा के केंद्र में युवाओं और समावेशी प्रतिभा विकास को रखा है। वैश्विक चुनौतियों, नवाचार प्रदर्शनों और नीतिगत संवादों के माध्यम से, यह शिखर सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे युवा नवप्रवर्तक और महिला उद्यमी जनहित के लिए जिम्मेदार, स्केलेबल एआई समाधानों को आकार दे रही हैं।

भारत के व्यापक एआई विजन के केंद्र में युवा:

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, भारत की व्यापक एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण में युवा सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। भारत के व्यापक एआई और डेटा से प्रभाव बढ़ाना सत्र में गहन अनुसंधान प्रतिभा, सतत नवाचार इको-सिस्टम और भारत के भाषायी और विकासात्मक संदर्भों के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस क्षेत्र के दिग्गजों ने इस बात पर बल दिया कि युवा नवोन्मेषकों को पारदर्शी, समझने योग्य और राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल द्वारा एआई प्रणालियां बनाने में सक्षम होना चाहिए जो वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें। उन्नत एआई अनुसंधान को कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जोड़कर, यह शिखर सम्मेलन भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई समाधानों के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित कर रहा है।

एल्गोरिदम से परिणाम तक:

शिखर सम्मेलन में, मापनयोग्य सार्वजनिक प्रभाव प्रदान करने वाली एआई के निर्माण पर विशेष बल देकर युवाओं की भागीदारी को मजबूत किया जा रहा है। ₹एल्गोरिदम से परिणाम तक₹ सत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एआई मिशन को कंप्यूट, मॉडल और डेटा को उपयोग योग्य अनुप्रयोगों में परिवर्तित करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में 600 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियों द्वारा प्रदर्शित एआई समाधानों के साथ, शिखर सम्मेलन युवा नवप्रवर्तकों को मापनयोग्य इस्तेमाल के मामलों और सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या-समाधान का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। वैश्विक विशेषज्ञों के साथ चर्चाओं ने कठोर मूल्यांकन, जिम्मेदार विस्तार और साक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन के महत्व से अवगत कराया, जिससे युवाओं को न केवल प्रौद्योगिकीविदों के रूप में, बल्कि परिणाम-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित एआई प्रणालियों में योगदानकताओं के रूप में स्थापित किया गया।

युवाएआई ग्लोबल यूथ चैलेंज:

युवाएआई ग्लोबल यूथ चैलेंज, इंडियाएआई मिशन की एक प्रमुख पहल है, जो 13 से 21 वर्ष की आयु के युवा नवप्रवर्तकों को 'लोग, ग्रह और प्रगति' के उद्देश्यों के अनुरूप एआई समाधान विकसित करने के लिए सशक्त बना रही है। 38 देशों से 2,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से इस चैलेंज में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, सुलभता, डिजिटल विश्वास और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाली 70 उच्च-क्षमता वाली टीमों ने भाग लिया। विजेता टीमों को राष्ट्रीय मान्यता के साथ-साथ वित्तीय पुरस्कार और सुव्यवस्थित इको-सिस्टम की सहायता भी मिली, जिसमें मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और उद्योग से जुड़ाव शामिल हैं। तकनीकी मजबूती, तैनाती की तैयारी और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित कठोर मूल्यांकन के माध्यम से, यह शिखर सम्मेलन प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे युवा नेतृत्व वाली एआई नवाचार प्रोटोटाइप से लेकर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित के समाधानों तक पहुंच सकती है, जिससे जिम्मेदार और समावेशी एआई में भारत का नेतृत्व मजबूत हो रहा है।

एआई बाय हर ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज:

ह्यएआई बाय हरह्व ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज ने भारत के जिम्मेदार एआई आंदोलन में महिलाओं और युवा नवोन्मेषकों को अग्रणी स्थान दिया। पैनल चर्चाओं, स्टार्टअप प्रदर्शनियों और त्वरित प्रस्तुति सत्रों के माध्यम से, कार्यक्रम ने दिखाया कि कैसे सहानुभूति-आधारित नवाचार स्वास्थ्य सेवा, जलवायु अनुकूलन, शिक्षा, फिनटेक, सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में व्यापक समाधानों में परिवर्तित हो सकता है। स्कूली स्तर के समस्या समाधानकर्ताओं से लेकर डीप-टेक संस्थापकों तक, प्रतिभागियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे विश्वास, क्षेत्र-विशिष्ट डिजाइन और मजबूत डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एआई मापनयोग्य सामाजिक परिणाम प्रदान कर सकता है। 150 महिला-नेतृत्व वाले एआई स्टार्टअप के लिए एक समर्पित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम की घोषणा ने शिखर सम्मेलन की पहुंच से तीव्रता की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि युवा और महिला नवोन्मेषकों को विचार से लेकर विस्तार तक हर चरण में समर्थन मिले।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर वैश्विक संवाद - श्रम बाजार की मजबूती के लिए डेटा:

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन आयोजित सत्र ₹कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर वैश्विक संवाद ‑ श्रम बाजार की मजबूती के लिए डेटा₹ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से अपनाने के संदर्भ में काम और रोजगार परिदृश्यों की बदलती प्रकृति और इस परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक नीतिगत विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उभरते अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों के आधार पर, चर्चा में विभिन्न आयु समूहों, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभावों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें प्रारंभिक रुझान उच्च एआई एक्सपोजर वाली भूमिकाओं में युवा श्रमिकों पर रोजगार के दबाव को दर्शाते हैं।

एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक:

एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक का शुभारंभ भारत भर में विकसित 100 से अधिक एआई समाधानों का एक समेकित संग्रह उपलब्ध कराकर युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संकलन स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, बुनियादी मॉडल और अत्याधुनिक एआई में नवाचारों को उजागर करता है, जो भारतीय स्टार्टअप की बढ़ती परिपक्वता और वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। मंत्रालयों और राज्यों में प्रभावशाली उपयोग मामलों के मूल्यांकन और विस्तार के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाकर, यह पहल युवा नवोन्मेषकों को पायलट परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है। अगले 12-18 महीनों में भारत को ₹उपयोग का केन्द्र₹ बनाने के लक्ष्य पर जोर देते हुए, शिखर सम्मेलन ने युवा नेतृत्व वाले एआई नवाचार को मापनयोग्य, वास्तविक दुनिया के परिणामों में परिवर्तित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सामूहिक रूप से, ये पहलें युवा नेतृत्व और महिला-पुरुष आधारित विविधता द्वारा संचालित भविष्य के लिए तैयार, समावेशी एआई इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। नवाचार प्लेटफार्मों को नीतिगत सहभागिता और इकोसिस्टम के समर्थन के साथ जोड़कर, शिखर सम्मेलन ने युवा प्रतिभाओं के लिए सतत विकास और वैश्विक एआई प्रभाव को आगे बढ़ाने के मार्ग को मजबूत किया।

भारत में एआई के क्षेत्र में प्रतिभा-आधारित नेतृत्व के वैश्विक संकेतक

2047 तक विकसित भारत के विजन की राह पर अग्रसर भारत में अब 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप महानगरों से बाहर उभर रहे हैं, जिससे यह मिथक टूट रहा है कि भारत में नवाचार केवल महानगरों तक ही सीमित है।

युवा नेतृत्व वाले एआई नेतृत्व को दशार्ने वाले वैश्विक संकेतक:

- एआई कौशल का उच्च प्रसार: स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में एआई कौशल का सापेक्ष प्रसार, समान व्यवसायों में वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक है, जो प्रारंभिक और व्यापक कौशल विकास पहलों के प्रभाव को दशार्ता है।
- उद्यमों द्वारा व्यापक स्वीकृति: नैसकॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार, भारत में 87 प्रतिशत उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे एआई-योग्य युवाओं की निरंतर मांग बनी हुई है और शिक्षा एवं कार्यस्थल के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं।
- युवा शक्ति: भारत में डिजिटल रूप से अनुकूलनीय युवाओं का विश्व का सबसे बड़ा समूह है, जो युवाएआई जैसे एआई शिक्षण और नवाचार कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को सक्षम बनाता है।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

युवाओं की भागीदारी नवाचार से आगे बढ़कर जिम्मेदार एआई अपनाने तक फैली, क्योंकि भारत ने 24 घंटों में 25 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाओं के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडियाएआई मिशन के तहत चलाए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान ने छात्रों और नागरिकों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह एआई उपयोग के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। इंटरैक्टिव परिदृश्यों के माध्यम से डेटा गोपनीयता, गलत सूचना और जवाबदेही पर चिंतन को प्रोत्साहित करके, इस पहल ने युवाओं को विश्वसनीय एआई के संरक्षक के रूप में स्थापित किया। व्यापक भागीदारी जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता की बढ़ती संस्कृति से अवगत कराती है, जो मानव-केंद्रित और नैतिक रूप से आधारित एआई इकोसिस्टम के भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

ये सभी संकेतक मिलकर यह दशार्ते हैं कि युवाएआई किस प्रकार एक व्यापक राष्ट्रीय इकोसिस्टम के भीतर कार्य करता है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और भविष्योन्मुखी है। प्रारंभिक एआई एक्सपोजर को मजबूत वैश्विक रैंकिंग, उद्यम स्तर पर इसके उपयोग और जनसांख्यिकीय पैमाने से जोड़कर, भारत अपने युवाओं को वैश्विक एआई परिदृश्य में सक्रिय भागीदार और भविष्य के नेताओं के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे जिम्मेदार और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में देश की भूमिका मजबूत हो रही है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भारत की युवा शक्ति एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर रही है। निरंतर नीतिगत समर्थन, व्यापक कौशल विकास पहलों और लोकतांत्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, देश अपनी युवा शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रतिभा इकोसिस्टम में परिवर्तित कर रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस बात पर जोर देता है कि कैसे युवा नेतृत्व वाली नवाचार, जिम्मेदारीपूर्ण एआई अपनाने और उद्योग समन्वय समावेशी और परिणामोन्मुखी विकास को गति देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, अपनी युवा आबादी को एआई क्षमताओं से सशक्त बनाना दीर्घकालिक उत्पादकता, अनुकूलन और वैश्विक नेतृत्व के लिए केंद्रीय महत्व रखता है।

प्रमुख विशेषताएं

- भारत का जनसांख्यिकीय लाभ इसके एआई परिवर्तन को शक्ति प्रदान कर रहा है, जिसमें 35 वर्ष से कम आयु की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या देश की डिजिटल और नवाचार रणनीति के केंद्र में है।
- विद्यालयों, व्यावसायिक प्लेटफॉर्मो, उन्नत अनुसंधान फेलोशिप और उद्योग साझेदारों तक व्याप्त राष्ट्रीय पहलों के समर्थन से एआई कौशल व्यापक स्तर पर प्रगति कर रहा है
- इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत किफायती एआई बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन महानगरों से परे कंप्यूट, डेटा और नवाचार के अवसरों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहा है।
- युवाओं के नेतृत्व वाला नवोन्मेष, प्रयोग से वैश्विक प्रभाव की ओर बढ़ रहा है, जिससे भारत ज़िम्मेदार, सबको साथ लेकर चलने वाले और यूज-केस पर आधारित एआई नेतृत्व के लिए एक उभरता हुआ केन्द्र बन रहा है।

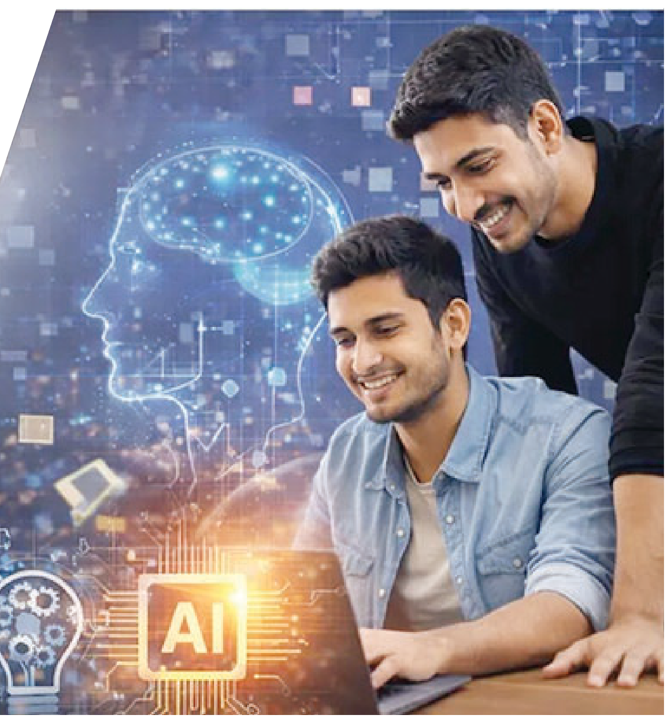

झारखंड के बजट में कृषि विभाग के लिए 4,884 करोड़ रुपये का प्रावधान : शिल्पी नेहा

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सदन में पारित 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट राज्य के भविष्य को नई दिशा देगा। इस कुल बजट में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने मंगलवार को सदन परिसर में कहा कि यह बजट विशेष रूप से किसानों, महिला कृषकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत महिला किसानों को एकीकृत कृषि मॉडल से जोड़ा जाएगा और आधुनिक तकनीक की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा।

मंत्री तिर्की ने बताया कि आउटकम बजट के आधार पर इस वर्ष 17 विभागों की 232 महिला संबंधित योजनाओं को शामिल करते हुए जेंडर बजट तैयार किया गया है। इसके तहत कुल 34 हजार 211 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि आधारित है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत पिछली तिमाही के 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है।

मंत्री ने बताया कि बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के लिए बजट 95 करोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये किया गया है। मृदा एवं जल संरक्षण के तहत बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के लिए 475 करोड़ 50 लाख रुपये प्रस्तावित है। कृषि समृद्धि योजना (सौर ऊर्जा आधारित) के लिए 75 करोड़ रुपये, कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये, जिसके तहत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट, रीपर और ट्रांसप्लांटर वितरित किए जाएंगे। झारखंड राज्य मिलेट मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये। नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये तथा राज्य उद्यान विकास योजना के तहत 245 करोड़ 80 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

पशुपालन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गिरिडीह और सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट और उच्च क्षमता वाले मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में लैंप्स/पैक्स में सहकारी विपणन परिसर सह सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार रुपये का प्रावधान है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 100 एमटी के 48 गोदाम, 500 एमटी के 24 गोदाम और 2500 एमटी के 72 गोदाम बनाए जाएंगे, जिस पर 160 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास और जीर्णोद्धार योजना के लिए 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह बजट कृषि क्षेत्र में समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा झारखंड को आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

वन्दे मातरम के 150 वर्ष स्मरणोत्सव पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बिभा संवाददाता

मेदिनीनगर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केन्द्रीय संचार ब्यूरो, डालटनगंज की ओर से वर्ष भर चलने वाले वन्दे मातरम के गौरवपूर्ण 150 वर्ष के स्मरणोत्सव, एक पेड़ मां के नाम एवं स्वच्छ भारत अभियान विषय पर आज राजकीयकृत ब्राह्मण प्लस टू उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प तथा कन्या पूजन के साथ हुई। इसके उपरांत क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री गौरव कुमार पुष्कर ने अतिथियों का परिचय कराते हुए विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने और मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव को सशक्त करने वाला अमर मंत्र है। बतौर अतिथि उपस्थित पर्यावरणविद् एवं वनराखी मूवमेंट के प्रणेता श्री कौशल किशोर जायसवाल ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पर्यावरण धर्म के आठ मूल मंत्रों की जानकारी देते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान किया। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात मिश्र सुमन ने वन्दे मातरम के पलामू से ऐतिहासिक जुड़ाव पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन्दे मातरम के रचयिता बंकिम चन्द्र चटर्जी के बड़े भाई संजीव चट्टोपाध्याय, जो पलामू में मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, ने ह्यपलामूह्ल नाम से बांग्ला में एक प्रसिद्ध यात्रा-वृत्तांत लिखा था। पत्रकार श्री सतीश चंद्र मिश्र 'सुमन' ने कहा कि वन्दे मातरम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने सेल्फी बूथ पर फोटो खिंचाकर ह्यवन्दे मातरमह्ल का सामूहिक गान करते हुए भारत माता को नमन किया। इस अवसर पर सामूहिक स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई।

विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को राष्ट्रभावना और ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक श्री संतोष कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सतीश कुमार दुबे ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार सहायक श्री मनोज कुमार सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित निबंध, रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कैबिनेट ने 9,072 करोड़ की तीन रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,072 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की हुई बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण, पुनारख-किऊल तीसरी एवं चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी एवं चौथी लाइन शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करेंगी और इनके माध्यम से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

इन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 5,407 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिनकी कुल आबादी करीब 98 लाख है। लाइन क्षमता में वृद्धि से परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम होगी। परियोजनाएं प्रधानमंत्री की न्यू इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय विकास को गति देंगी और रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि कर स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगी।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत योजना और बहु-मोडल संपर्क को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सुगम होगी। क्षमता विस्तार से जबलपुर स्थित कचनार शिव मंदिर, बालाघाट का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, धुआंधार झरना, चांडिल बांध तथा दलमा वन्यजीव अभयारण्य जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क और बेहतर होगा।

ये मार्ग कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, सीमेंट, फ्लाई ऐश, उर्वरक, खाद्यान्न और पेट्रोलियम पदार्थ (पीओएल) जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता वृद्धि से लगभग 52 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन साधन होने के कारण इन परियोजनाओं से देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, तेल आयात में लगभग 6 करोड़ लीटर की बचत होगी तथा लगभग 30 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को (सीसीईए) विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नए ह्यसेवा तीर्थह्ल में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीसीईए ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी पिछले विपणन सीजन 2025-26 के मुकाबले 275 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी विपणन सीजन 2014-15 के 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर विपणन सीजन 2026-27 में 5,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 3,525 रुपये प्रति क्विंटल यानी (2.5 गुना) की बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपणन सीजन 2014-15 से विपणन सीजन 2025-26 के दौरान जूट उगाने वाले किसानों को दी गई एमएसपी रकम 1342 करोड़ रुपये थी, जबकि विपणन सीजन 2004-05 से विपणन सीजन 2013-14 के दौरान दी गई रकम 441 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत पर 61.8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुसार है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी बनी रहेगी और ऐसे ऑपरेशन में अगर कोई नुकसान होता है तो केंद्र सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी।

पावर ग्रिड सहायक कंपनियों में कर सकेगी ज्यादा निवेश

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अपनी सहायक कंपनियों में निवेश करने की सीमा 5 हजार से बढ़ा कर 7.5 हजार करोड़ कर दी है। इस मंजूरी से पावरग्रिड को अपने मुख्य व्यवसाय में निवेश बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे गैर-जीवाश्म-आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस मंजूरी से पावरग्रिड की प्रति सहायक कंपनी इक्विटी निवेश की अनुमति सीमा मौजूदा 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 7.5 हजार करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि कंपनी की कुल संपत्ति के 15 प्रतिशत की मौजूदा सीमा बनी रहेगी। अब पावरग्रिड पूंजी-गहन ट्रांसमिशन परियोजनाओं, जैसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बोलियों में भाग ले सकता है। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं के चयन हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। इससे बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होगा और अंततः उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।

केंद्र ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके पूरा होने पर हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नए सेवा तीर्थ में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि 73.18 एकड़ क्षेत्र में 71,500 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा संरचना का उपयोग होगा। विमान पार्किंग क्षेत्र का विस्तार कर 15 विमान पार्किंग बे बनाए जाएंगे, जिनमें एक वाइडबॉडी (कोड ई) बे भी शामिल होगा। मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा में 1,000 कारों की क्षमता होगी। नया टर्मिनल पीक आवर्स में 2,900 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों तक होगी। परियोजना को 5-स्टार ग्रिहा (एकीकृत आवास मूल्यांकन की हरित रेटिंग) रेटिंग हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इससे श्रीनगर की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और डल झील, शंकराचार्य मंदिर तथा मुगल गार्डन्स जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।

कोलकाता और लालकुआं के बीच होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

आसनसोल : रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए कोलकाता और लालकुआं के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। 05060 लालकुआं - कोलकाता स्पेशल 5.03.2026 और 26.03.2026 के बीच (4 ट्रिप) हर गुरुवार को लालकुआं से 13:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन 23:55 बजे कोलकाता पहुँचेगी तथा 05059 कोलकाता - लालकुआं स्पेशल 7.03.2026 और 28.03.2026 के बीच (4 ट्रिप) हर शनिवार को कोलकाता से 05:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन 15:45 बजे लालकुआं पहुँचेगी। उक्त ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान अपने मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के दुगार्पुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित कोच की सुविधा उपलब्ध होगी।

उपराष्ट्रपति आज से जम्मू-कश्मीर के दौरे पर

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 25-26 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को बताया कि इस दौरान वह 26 फरवरी को कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय परिसर स्थित कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाला यह समारोह संस्थान और उसके विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कश्मीर घाटी की उनकी यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जिससे समारोह का महत्व और बढ़ गया है।

चुनाव आयोग ने 27 साल बाद आयोजित किया राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

मतदाता हमारे केंद्र में : सीईसी

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन में 27 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग (ईसीआई) और राज्य चुनाव आयुक्त एक साथ आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने यहां भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय हित और संवैधानिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को मिलकर काम करना चाहिए और हर निर्णय में मतदाता को केंद्र में रखना चाहिए।

इस अवसर पर चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधु और डॉ. विवेक जोशी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया और विचार-विमर्श की रूपरेखा प्रस्तुत की। आयोग ने लोकतंत्रों का संगम नामक पुस्तक का लोकार्पण भी किया।

उल्लेखनीय है कि सम्मेलन में ईवीएम, ईसीआईनेट और मतदाता सूची साझा करने पर प्रस्तुति दी जाएंगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी मतदाता सूची प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और संस्थागत समन्वय को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।

इन चचाओं का मुख्य केंद्र एक मतदाता सूची की अवधारणा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संवैधानिक आदेशों द्वारा शासित अधिकार क्षेत्रों में मतदाता आंकड़ों की एकरूपता सुनिश्चित करना है।

तेलंगाना में चार माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

एजेंसी

हैदराबादः प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के चार वरिष्ठ कार्यकताओं ने मंगलवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवधर रेड्डी की उपस्थिति में मुख्यधारा में लौट आए।

पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वालों में पोलित ब्यूरो सदस्य टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी उर्फ कुम्मा दादा, सेंट्रल कमेटी सदस्य मल्लराजी रेड्डी उर्फ संग्राम उर्फ रंगाराम, तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर उर्फ जगन तथा स्टेट कमेटी सदस्य नून नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना उर्फ रन्ना दादा शामिल हैं।

डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दो वर्षों में कुल 591 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। इनमें चार सेंट्रल कमेटी सदस्य, 16 राज्य कमेटी सदस्य, 26 डिवीजन कमेटी सदस्य एवं सचिव, 85 एसीएस तथा 60 अन्य सक्रिय सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जन्मे और पले-बढ़े 11 माओवादी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ वार्ता कर रहे हैं और उनके भी जल्द आत्मसमर्पण करने की संभावना है।

डीजीपी ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आह्वान पर कई माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सार्वजनिक जीवन में लौटने की इच्छा जताई है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को घोषित इनाम राशि और पुनर्वास पैकेज तत्काल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है-जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा।

इस अवसर पर डीजीपी ने सरेंडर में अहम भूमिका निभाने वाली स्पेशल इंटेलिजेंस की महानिरीक्षक (आईजी) सुमति और उनकी टीम की सराहना की। साथ ही इंटेलिजेंस के महानिदेशक विजय कुमार को भी बधाई दी।

दरअसल,पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी उर्फ टिप्पिरी तिरुपति के आत्मसमर्पण को माओवादी आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तिरुपति जगतियाल जिले के कोरुतला स्थित अंबेडकर नगर के निवासी हैं। वे वर्ष 1983 में माओवादी आंदोलन से जुड़े और धीरे-धीरे संगठन में शीर्ष पदों तक पहुंचे। दक्षिण भारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तिरुपति का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल रहा है। संगठन में उन्हें संजीव, चेतन, रमेश, सुदर्शन और देवन्ना जैसे नामों से भी जाना जाता था।

पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए माओवादी हमले, जिसमें 74 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हुए थे, उसके पीछे तिरुपति को मास्टरमाइंड माना जाता है। नंबाला केशव राव की मौत के बाद सितंबर 2025 में तिरुपति को संगठन का महासचिव बनाया गया था। उनके आत्मसमर्पण के बाद

पुनारख-किउल के मध्य तीसरी और चौथी लाईन के निर्माण को भी मिली मंजूरी

भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी

कुल 9,072 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी

हाजीपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी । इनमें पुनारख-किऊल तीसरी और चौथी लाइन, गोंदिया-जबलपुर लाइन दोहरीकरण एवं गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं ।महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों में संपर्क में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है।

विदित हो कि रेल यात्रा सुगम हो साथ ही मालगाड़ी की आवाजाही भी सुगमतापूर्वक किया जा सके इसके लिए रेलवे द्वारा रेल आधारभूत संरचना में वृद्धि का कार्य निरंतर जारी है ।इसी कड़ी में 17 हजार करोड़ रूपए की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा के मध्य लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाईन का निर्माण किया जाना है जिसमें वर्तमान में डीडीयू से किउल तक तीसरी और चौथी रेल लाईन जबकि किउल से झाझा तक तीसरी रेल लाईन का निर्माण किया जाना है। इस पूरी परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य सुगमतापूर्वक तेजी से पूरा करने के लिए इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल तथा किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है ।

इसके तहत प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर (24 किमी) तथा बख्तियारपुर से पुनारख (30 किमी) की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गयी थी जिसमें बख्तियारपुर-पुनारख निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।आज 50 किमी लंबे पुनारख से किऊल के मध्य तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है । शेष रेलखंडों की स्वीकृति विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा रेल लाईन का निर्माण 1860-70 के दशक में किया गया था । तत्पश्चात इसका दोहरीकरण किया गया। तब से अब तक कई दशकों के मध्य जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के मद्देनजर यात्री गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती चली गयी । इसके फलस्वरूप ट्रैकों की क्षमता से कई गुणा अधिक गाड़ियों के परिचालन से ट्रैकों के रख-रखाव एवं समय पालन में कठिनाइयां आती थीं ।इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ट्रैकों की क्षमता में वृद्धि अति आवश्यक था ।इन्हीं के मद्देनजर मालगाड़ियों के परिचालन हेतु पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर तथा तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है।इन लाइनों के निर्माण से मालगाड़ी के साथ-यात्री गाड़ियों का परिचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा साथ ही काफी संख्या में अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।इससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी जो औद्योगिकीकरण वृद्धि में सहायक होगा ।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट,भोसले गली,हरिहर सिंह रोड,बरियातु,रांची-834009(झारखंड) दूरभाषः 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा शिवा साई पब्लिकेशन प्रा.लि. (एसएच प्रिंटर प्रा.लि.), काठीटांड रातु, नियर टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप, रातु, रांची - 835222 झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू**(*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली** ।
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com